हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 283 बेमेतरा, मंगलवार 09 जून 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

661 करोड़ रुपए के सरकारी फंड घोटाले में सीबीआई की छापेमारी

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े सरकारी फंड के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर समेत छह जगहों पर छापे मारे। जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाने, फंड ट्रांसफर करने और बाद में उसे दूसरी जगह भेजने में मदद की थी। तलाशी अभियान चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-एनसीआर स्थित परिसरों में चलाया गया। इसमें हरियाणा कैडर के सीनियर सरकारी अधिकारियों और विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर के घर और ऑफिस शामिल थे। सीबीआई के अनुसार, जांच में सामने आया है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर खातों के खुलवाने, धनराशि के हस्तांतरण और बाद में उसके दुरुपयोग में सहायता की। आरोप है कि उन्हें इस मदद और कार्रवाई न करने के बदले गलत तरीके से फायदा मिला। पता चला कि नोएडा की विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को अपराध से मिली रकम अपने अकाउंट में मिली थी।

रफ्तार पकड़ रहा मॉनसून, केरल के बाद 4 राज्यों में दस्तक

नई दिल्ली। देशभर में भीषण गर्मी से बेहाल लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। 4 जून को केरल तट से टकराने के बाद दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। केरल में एंट्री के महज 24 घंटे के भीतर मॉनसून देश के 4 राज्यों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के अनुसार, 5 जून को मॉनसून गोवा के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के अधिकांश इलाकों, तमिलनाडु और अरब सागर के मध्य हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इन राज्यों में एंट्री के साथ ही कई जगहों पर तेज बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। अब यह गोवा से महाराष्ट्र की ओर कूच कर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए ताजा बुलेटिन के मुताबिक, मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए मौसमी परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई हैं।

अब अखबार में परोसा खाना तो होगी कार्रवाई

मुंबई । अगर आप भी सड़क किनारे ठेले या फूड स्टॉल पर अखबार में लिपटा हुआ गरमा-गरम वड़ा-पाव, समोसा, कचौड़ी या चाट बड़े चाव से खाते हैं, तो अब आपको अपनी यह आदत तुरंत बदलनी होगी। आपकी यह छोटी सी लापरवाही आपको किसी गंभीर बीमारी का शिकार बना सकती है। इस मामले पर बड़ा संज्ञान लेते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने देश भर में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। स्नस्ड्ड ने देश के सभी खाद्य विक्रेताओं, रेस्तरां मालिकों, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए एक सख्त गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत खाने-पीने की चीजों को अखबार में पैक करने या उसमें परोसने पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह देशव्यापी सख्त फैसला हाल ही में मुंबई में हुई एक बड़ी और औचक कार्रवाई के बाद सामने आया है।

इंडिया ब्लॉक की 7वीं बैठक संपन्न

विपक्ष की एकजुटता ही सरकार को चुनौती देगी-मल्लिकार्जुन.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक आज दिल्ली में आयोजित की गई. जिसमें हालिया विधानसभा चुनाव के बाद की रणनीति समेत कई मुद्दों पर मंथन किया गया. वहीं, विधानसभा चुनावों में पार्टियों के बीच मतभेद का असर भी इस पर दिखा है. दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की यह 7वीं बैठक रही. विपक्षी दलों की इस अहम बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हर 2 महीने में गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी. हमारी अगली बैठक हैदराबाद में बुलाई जाएगी. आज की अहम बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है. इसके तहत एसआईआर के मसले पर हम मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे. साथ ही हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. खरगे ने आज सोमवार को कहा कि बैठक में 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है. पहला, वोट लूट के खिलाफ चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जाएगा. दूसरा, नीट यूजी पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) को तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए. तीसरा, आर्थिक हालत पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए. चौथा, हर 2 महीने में हमारी बैठक होगी, इसकी अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को होगी. पांचवां, संसद में सभी पार्टियों का कॉर्डिनेशन जारी रहेगा. बैठक के बाद खरगे ने कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक में 25 पार्टियां शामिल हुईं. उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन भी वर्चुअली मीटिंग में शामिल हुए और अपने विचार शेयर किए. वे भी इन सभी मुद्दों पर सहमत हैं. इसके बाद, हम पांच पॉइंट्स पर आम सहमति पर पहुंचे. हम आज सहमत हुए हैं; हम इन मुद्दों के लिए लड़ेंगे, उन पर काम करेंगे, और आगे बढ़ेंगे. खरगे ने कहा, एसआईआर, वोट लूट और चुनाव में चोरी पर मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजने पर सहमति बनी. यह पत्र बहुत जल्द मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा. दूसरा पॉइंट, शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग करने पर एकमत से सहमति बनी, क्योंकि उन्होंने नीट और सीबीएसई एग्जाम देने वाले लाखों युवाओं के साथ धोखा किया. बता दें कि, चर्चा थीं कि तमिलनाडु में विजय की सरकार में शामिल होने के बाद टीवीके भी इस बैठक में शामिल होगी लेकिन पार्टी ने इस बैठक से फिलहाल दूरी बना ली है. दरअसल, उन्हें इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था. इस बैठक में केवल उन्हीं पार्टियों को बुलाया गया था जिनके सांसद संसद में मौजूद हैं. टीवीके खरगे ने कहा कि एसआईआर के कारण हमारे करोड़ों लोगों से उनका मताधिकार छीना जा रहा है. संविधान पर हमला लगातार जारी है. जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और डराने-धमकाने के औजार के रूप में लगातार किया जा रहा है. गैर-बीजेपी सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आर्थिक माहौल बेहद नकारात्मक है. नई नौकरियां पैदा करने के लिए जिस रफ्तार से नए निवेश आने चाहिए, वे बिल्कुल उस रफ्तार से नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और एमएसएमईएस का भविष्य गंभीर संकट में है. परीक्षा प्रणाली के पूर्ण कुप्रबंधन के कारण हमारे लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है.

गैर-भाजपा सरकारों के साथ भेदभाव....

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि गैर-भाजपा सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आर्थिक माहौल बेहद नकारात्मक है। नई नौकरियां पैदा करने के लिए जिस रफ्तार से नए निवेश आने चाहिए, वे बिल्कुल उस रफ्तार से नहीं आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और एमएसएमई का भविष्य गंभीर संकट में है। परीक्षा प्रणाली के पूर्ण कुप्रबंधन के कारण हमारे लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार, खासकर भाजपा शासित राज्यों में लगातार जारी हैं। हमारी विदेश नीति के साथ पूरी तरह से समझौता किया गया है और उन पारंपरिक मूल्यों को कायम नहीं रखा गया है। जिनका भारत लंबे समय से पुरजोर समर्थन करता रहा है।

एसआईआर के जरिए करोड़ों लोगों का वोट कटा'

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अब हमें उसी भावना को और मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है, ताकि केंद्र सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने खड़ी कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके। एसआईआर के कारण करोड़ों लोगों से उनका मताधिकार छीना जा रहा है। संविधान पर हमला लगातार जारी है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और डराने-धमकाने के औजार के रूप में लगातार किया जा रहा है।

बैठक में शामिल हुईं ये पार्टियां

बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) लिबरेशन, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, विदुथलाई चिरुथैगल काची, मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, केरल कांग्रेस, केरल कांग्रेस (रू), राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, लोक दल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और शेतकारी कामगार पक्ष शामिल हुए. पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की पहली बैठक थी.

10 जून को टूटेगा नेहरू का रिकॉर्ड

गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए सीधे गरीबों की मदद-पीएम मोदी

नई दिल्ली/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का केंद्र गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग का कल्याण रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित हैं। इसका उद्देश्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 12 वर्ष गरीब कल्याण हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जन धन योजना, सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में राशि (डीबीटी), स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उद्देश्य लोगों को सम्मानजनक जीवन और बेहतर अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की हर योजना का लक्ष्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें सशक्त बनाना रहा है। उन्होंने बताया कि डीबीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार व लीकेज में कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक के उपयोग से शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी बनी है और लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। 10 जून को वह लगातार 4,399 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। इसके साथ ही वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। नेहरू ने पहले आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,398 दिन तक पद संभाला था। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।

प्रधानमंत्री मोदी बनाएंगे नया रिकॉर्ड

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। 10 जून को वह लगातार 4,399 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। इसके साथ ही वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। नेहरू ने पहले आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,398 दिन तक पद संभाला था। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल की।

टीएमसी को बड़ा झटका

राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने टीएमसी से दिया इस्तीफा...

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा की सदस्यता और टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए और हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार को 15 वर्षों के कथित अराजक शासन का परिणाम बताया। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भारी जनादेश देकर टीएमसी के 15 साल के शासन को समाप्त करने का फैसला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, उद्योगों की कमी, कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति और रोजगार के अवसरों की कमी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती रहीं। सुखेंदु शेखर ने कहा कि जनता के ऐतिहासिक फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने राज्यसभा और टीएमसी दोनों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने नई भाजपा सरकार की भी सराहना की और कहा कि सरकार अपने चुनावी घोषणापत्र के अनुसार पश्चिम बंगाल के विकास और पुनर्निर्माण के लिए कदम उठा रही है। सुखेंदु शेखर रॉय का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब टीएमसी के भीतर लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान और असंतोष की चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी के कई सांसद और विधायक नेतृत्व से नाराज हैं।

रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा टला, केदारनाथ जा रही कार नदी किनारे गिरी

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। तिलवाड़ा पेट्रोल पंप के समीप केदारनाथ धाम की ओर जा रही एक महिंद्रा एक्सयूवी 700 अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 50 मीटर नीचे नदी किनारे पानी में जा गिरी। वाहन में सवार पांच यात्रियों को पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जबकि तीन अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह पांच बजे स्थानीय प्रशासन को दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रुद्रप्रयाग पुलिस, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), डीडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस सेवा की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

सुप्रीम कोर्ट में अब होगी एआई की एंट्री

यह कभी जजों की जगह नहीं ले सकता-सीजेपी सूर्यकांत...

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारतीय न्याय व्यवस्था में अब एआई की एंट्री होने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने भारत की अदालतों में एआई के औपचारिक इस्तेमाल को लेकर रेगुलेशन्स फार यूज ऑफ एआई इन कोर्ट 2026 का ड्राफ्ट जारी कर सभी हितधारकों और आमजनता से सुझाव भी आमंत्रित किये है. भारतीय न्याय व्यवस्था में हो रहे इस व्यापक बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने प्रौद्योगिकी को हमेशा इंसानी सोच-समझ में मदद करने के साधन के रूप में देखा है, ना कि न्यायाधीशों की स्वतंत्र सोच और फैसले लेने की क्षमता के विकल्प के रूप में. सीजेपी सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय परिस्थितियों और मूल्यों के अनुरूप न्यायिक सिद्धांतों को विकसित करने पर काफी जोर दिया गया है. ऑक्सफोर्ड यूनियन और ऑक्सफोर्ड लॉ सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस टू डिजिटल रियलिटी: सेफगार्डिंग जस्टिस इन द एज ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विषय पर अपने संबोधन में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पहले से जारी प्रौद्योगिकी से जुड़ीं पहलों के अलावा, न्यायपालिका के लिए एक स्वदेशी एआई प्रणाली विकसित करने की संभावनाओं पर गंभीरता से काम किया जा रहा है. सीजेपी सूर्यकांत बोले, 'भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रौद्योगिकी को हमेशा इंसानी सोच-समझ में मदद करने के साधन के रूप में अपनाया है। न्यायाधीशों की स्वतंत्र सोच और फैसले लेने की क्षमता के विकल्प के रूप में नहीं.

सिंहदेव के बयान पर साय ने कसा तंज

कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है-मुख्यमंत्री.....

रायपुर। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष चयन को लेकर दिए गए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये हमारा देखने का काम नहीं है, कांग्रेस इसको देखे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कितना भी कर लें, जनता का विश्वास नहीं जीत पाएगी। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और लगातार सिमटती जा रही है, क्योंकि ये लोग हमेशा जनता को ठगने का काम करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जमीन-आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी वर्ष 2018 में प्रदेश की जनता ने इन्हें जनादेश दिया था, लेकिन पांच वर्षों तक इन्होंने केवल जनता को ठगने और प्रदेश को लूटने का काम किया। इसका परिणाम उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। अब ये लोग कुछ भी कर लें, जनता का विश्वास खो चुके हैं। वहीं एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की जो स्थिति है, उससे हम सब वाकिफ हैं।

आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा

प्लांट में पिघले हुए स्टील का रिसाव,8 मजदूरों की दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप-मुख्यमंत्री नायडू को लगा गहरा सदमा

विशाखापत्तनम ।एजेंसी

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट के एसएमएस-2 और एसटीसी-3 हीट फैसिलिटी में बड़ी मात्रा में पिघले हुए स्टील के रिसाव से 8 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। कई कर्मचारी घायल भी हुए हैं। यह हादसा बहुत उच्च तापमान वाले पिघले स्टील से भरे लेडल के फटने की वजह से हुआ। हादसे के बाद प्लांट में दहशत फैल गई, जिससे कर्मचारी और अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। स्टील प्लांट के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही स्टील प्लांट के उच्च अधिकारी, सुरक्षा दल और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे है। फिलहाल, पूरी यूनिट को खाली करा लिया गया है और सुरक्षा कर्मी राहत व बचाव कार्य में लग गए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर केसव राव ने एक मीडिया हाउस को बताया कि स्टील प्लांट के विशेषज्ञ कर्मी और फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं और रिसाव के कारण फैसिलिटी में लगी भीषण आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। घायलों में से कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिससे मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। राज्य गृह मंत्री वांगलापुडी अनीता ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हुए इस हादसे पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने विशाखापट्टनम जिला कलेक्टर और सिटी पुलिस आयुक्त से फोन पर बात की और दुर्घटना की पूरी जानकारी ली। गृह मंत्री ने अधिकारियों को घायलों का बेहतर ईलाज कराने के निर्देश दिए और दुर्घटना स्थल पर बचाव व राहत कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया। गृह मंत्री हादसे की खबर मिलते ही तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गई और लगातार अधिकारियों से फोन पर बात कर रही हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विशाख स्टील प्लांट में हुए हादसे से मुझे गहरा सदमा लगा है। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि इस हादसे में कई कर्मचारियों की जान चली गई है। मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की है और उन्हें सभी सरकारी विभागों के साथ मिलकर राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में साइट पर मौजूद कई कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए हैं। रिसाव के बाद आग लगने से कुछ कर्मचारियों के यूनिट के अंदर फंसे होने की आशंका है। फायर और इमरजेंसी सर्विस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने व बचाव कार्य में जुटी हैं। घायल और फंसे हुए कर्मचारियों की सही संख्या की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाला शातिर आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार, भेजा गया जेल

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर /:-उत्तर बस्तर कांकेर 08 जून 2026 कांकेर जिले के थाना नरहरपुर पुलिस को एक नाबालिग पीड़िता के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले के फरार आरोपी को हरियाणा राज्य से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कांकेर निखिल अशोक कुमार राखेचा के कड़े निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के कुशल मार्गदर्शन में अंजाम दी गई है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 14 अप्रैल 2026 को प्रार्थी द्वारा थाना नरहरपुर में अपनी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने बताया था कि उनकी बेटी 13 अप्रैल 2026 से अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसकी हर संभावित स्थान और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तब किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिए जाने की आशंका व्यक्त की गई। इस गंभीर शिकायत पर नरहरपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 85/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137 (2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया और पीड़िता की सरगर्मी से तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। थाना प्रभारी निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर लगातार सुराग जुटाने शुरू किए। सघन जांच और कड़े प्रयासों के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता तब मिली जब पीड़िता की लोकेशन बिहार में पाई गई। पुलिस टीम ने 18 मई 2026 को ग्राम जमुनिया, थाना बथवरिया, जिला पश्चिम चंपारण (बिहार) से नाबालिग पीड़िता को पूरी तरह सुरक्षित बरामद कर लिया। इसके बाद जब महिला पुलिस अधिकारी द्वारा नियमानुसार पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, तो मामले में एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मोड़ आया। पीड़िता ने अपने बयान में खुलासा किया कि आरोपी सुदामा कुमार चौधरी ने उसके नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद उसे बहलाया-फुसलाया, उसका अपहरण किया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के इस मर्मस्पर्शी कथन और मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना के दौरान प्रकरण में बीएनएस की धारा 87, 64(2)(ड) तथा पॉक्सो एक्ट की कड़ी धारा 4 एवं 6 को भी जोड़ा गया। इस खुलासे के बाद से ही आरोपी लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा था और फरार चल रहा था। हालांकि, नरहरपुर पुलिस ने हार नहीं मानी और आरोपी की लगातार पतासाजी की जाती रही। इसी बीच पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कहीं छिपा हुआ है। सूचना की तस्दीक होते ही थाना नरहरपुर की एक विशेष टीम तुरंत हरियाणा के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम ने फरीदाबाद के ग्राम निमका, थाना सदर बल्लभगढ़ में बेहद सतर्कता से घेराबंदी की और आखिरकार 21 वर्षीय शातिर आरोपी सुदामा कुमार चौधरी (पिता प्रभु चौधरी, निवासी ग्राम जमुनिया, थाना बथवरिया, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार) को धर दबोचा। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर थाना नरहरपुर लाकर गहन पूछताछ की गई, जिसमें अपराध में उसकी संलिप्तता पूरी तरह सिद्ध होने पर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस पूरे अंधे कत्ल जैसी गुत्थी को सुलझाने और आरोपी को दबोचने में थाना प्रभारी निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल, सहायक उपनिरीक्षक (साउनि) पल्टूराम मंडावी, आरक्षक डुमेश साहू, आरक्षक पवन मरकाम और आरक्षक जशवंत उइके की सराहनीय व अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनकी इस त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में जमकर प्रशंसा हो रही है।

10 जून को रिलीज होगा आलिया भट्ट-शर्वरी स्टारर 'अल्फा' का टीज़र, इसके बाद शुरू होगा यंग इंडिया के 'अल्फा एटीट्यूड' को सेलिब्रेट करने वाला दमदार मार्केटिंग अभियान

जित मुंबई/मूक पत्रिका

यश राज फिल्म्स 10 जून को आलिया भट्ट और शर्वरी अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अल्फा' की पहली झलक टीज़र के रूप में जारी करने जा रहा है। यह टीज़र एक ऐसी लड़की की ओरिजिन स्टोरी पर केंद्रित होगा, जिसे एक खतरनाक किलिंग मशीन बनने के लिए तैयार किया जाता है। वायआरएफ स्पाई यूनिवर्स की यह पहली ऐसी ओरिजिन स्टोरी है, जिसमें मुख्य किरदार एक असैसिन है। एक वरिष्ठ ट्रेड सूत्र ने बताया,÷अल्फा का टीज़र निश्चित रूप से 10 जून को रिलीज होगा। इसके बाद फिल्म के लिए एक आक्रामक मार्केटिंग और प्रमोशनल अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें कहानी को प्रचार का केंद्र बनाया जाएगा। यह अभियान आज के भारत के 'अल्फा एटीट्यूड' को सेलिब्रेट करेगा। आदित्य चोपड़ा और उनकी टीम ने एक बेहद सोच-समझकर बनाई गई रणनीति तैयार की है, जो फिल्म की रिलीज तक कई चरणों में सामने आएगी। सूत्र ने आगे कहा,÷अल्फा का पूरा अभियान इस विचार पर आधारित है कि 'अल्फा' सिर्फ एक किरदार या फिल्म का नाम नहीं, बल्कि एक सोच और रवैया है। कई प्रभावशाली सार्वजनिक प्रस्तुतियों, डिजिटल अभियानों, युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों और देशभर में होने वाली चर्चाओं के जरिए आलिया और शर्वरी उस सोच का जश्न मनाएंगी, जो आधुनिक भारत और उसकी युवा पीढ़ी को परिभाषित करती है – एक ऐसी पीढ़ी जो खुद को लेकर बिल्कुल बेझिझक है। सूत्र ने यह भी बताया,÷अल्फा का अभियान इस तरह से तैयार किया गया है कि लड़कियों को 'अल्फा' होने के विचार का पर्याय बनाया जा सके। आज की लड़कियां अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं और सामाजिक दबावों या अपेक्षाओं के दायरे में बंधने से इनकार कर रही हैं। इसलिए दर्शकों को एक मजेदार, कूल, बेबाक और एटीट्यूड से भरपूर अभियान देखने को मिलेगा।÷'द रेलवे मेन' फेम शिव रवैल द्वारा निर्देशित 'अल्फा' यश राज फिल्म्स की एक भव्य थिएटर रिलीज फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

खेत म लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धमाके की आवाज से मचा हड़कंप..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सरिया नगर पंचायत से लगे विनोद भोजनालय के पीछे सोमवार देर शाम ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि ट्रांसफार्मर से लगातार धमाके जैसी आवाजें आने लगीं, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए।प्राप्त जानकारी के अनुसार सरिया से कंचनपुर क्षेत्र के एक किसान द्वारा अपने खेत में पैरावट (पराली) में आग लगाई गई थी। यह आग धीरे-धीरे फैलते हुए खेत के पास स्थित ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई और कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर से तेज धमाके की आवाजें सुनाई देने लगीं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग सुरक्षित दूरी पर हट गए। बताया जा रहा है कि आग फैलते देख संबंधित किसान मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। फिलहाल घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

सरिया-परसरामपुर मार्ग पर दो बाइक की टक्क र में चार घायल, दो गंभीर; मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रेफर..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सरिया थाना क्षेत्र के सरियाङ्कपरसरामपुर मुख्य मार्ग पर सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे दो बाइक सवारों के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कुल चार लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम सुरसी निवासी पूर्व सरपंच आत्माराम साहा सरिया की ओर से खाद खरीदकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। वहीं दूसरी बाइक पर सवार ग्राम कोर्रा निवासी भुवनेश्वर राणा अपनी पत्नी सफेद बाई के साथ एकादश कर्म से लौट रहे थे। दुर्घटना में भुवनेश्वर राणा और उनकी पत्नी भी घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से 112 एंबुलेंस को सूचना दी गई, जिसके माध्यम से सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरिया पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद आत्माराम साहा और सफेद बाई की गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना के दौरान अचानक स्थिति बनने से यह हादसा हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि सड़क पर सामने से आ रहे वाहन और मोड़ के कारण टक्कर हुई, वहीं यह भी चर्चा रही कि एक घटना के दौरान जानवर (बिल्ली) के आने से स्थिति बिगड़ गई। हालांकि वास्तविक कारण की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सुशासन तिहार-2026: विकास खण्ड बेरला के ग्राम पंचायत लाटा में समाधान शिविर आज

बेमेतरा/मूक पत्रिका

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत 09 जून को जनपद पंचायत बेरला के ग्राम पंचायत लाटा के पंचायत भवन में समाधान शिविर आयोजित किया गया है। ग्राम लाटा कलस्टर में ग्राम खुड़मुड़ी, कंडरका, ढाबा, बेरलकला, भालेसर, लाटा, उफरा, हरदी, सरदा, भटगांव, बावनलाख, अतरगढ़ी, कुरूद, रांका, रवेली, तिवरैया, कठिया, खम्हरिया, टेमरी, किरीतपुर ग्राम पंचायत के लिए यह शिविर आयोजित किया गया है। शिविर का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे निर्धारित किया गया है। समाधान शिविर में विभिन्न योजनाओं से पात्र अनेक हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव निराकरण किया जाएगा। शिविर में विभिन्न विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। शिविर में शासन द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने ग्रामीण जनों को शिविर में उपस्थित होकर शिविर का लाभ लेने की अपील की है।

डबल इंजन की सरकार का बड़ा निर्णय : 1 जुलाई से 125 दिवस का गारंटीड रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ - अशीष जैन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 1 जुलाई से 125 दिवस का गारंटीड रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, छत्तीसगढ़ के प्रदेश सहप्रभारी श्री आशीष जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनकल्याण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 125 दिवस के गारंटीड रोजगार कार्यक्रम से प्रदेश के हजारों श्रमिक परिवारों को रोजगार प्राप्त होगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। श्री जैन ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना के विकास तथा आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डबल इंजन सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है और यह कार्यक्रम उसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि पात्र हितग्राही इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें तथा सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनें।

कांकेर जर्जर भवन में रहने को मजबूर छात्राएं, अलबेलापारा बालिका छात्रावास के नए भवन की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर /कांकेर जिला मुख्यालय के अलबेलापारा में संचालित सामान्य बालिका छात्रावास की छात्राओं को पिछले कई वर्षों से जर्जर भवन में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भवन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यहां कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इस गंभीर समस्या को लेकर छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपकर नए भवन की स्वीकृति देने की गुहार लगाई है। छात्राओं का कहना है कि यह छात्रावास पिछले 30 वर्षों से शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर एवं उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के अधीन संचालित हो रहा है, लेकिन लंबे समय से इसकी मरम्मत या नए भवन का निर्माण नहीं कराया गया है।

छात्रावास की अध्यक्ष मोनिका कोर्राम और अन्य छात्राओं ने बताया कि इस छात्रावास में दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से आई लगभग 50 छात्राएं रहकर पीजी कॉलेज कांकेर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। वर्तमान में भवन की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि छात्राओं के लिए यहां रहकर पढ़ाई करना बेहद दूभर हो गया है। विशेषकर बारिश के दिनों में छत से अत्यधिक पानी का रिसाव होता है, जिससे पूरे भवन में पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में छात्राओं को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने सामान और जान-माल की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। छात्राओं का कहना है कि नवीन भवन की मांग को लेकर उनके द्वारा पूर्व में भी शासन-प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, परंतु आज दिनांक तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। प्रशासन को सौंपे गए इस ज्ञापन के माध्यम से छात्राओं ने कलेक्टर से सादर निवेदन किया है कि छात्राओं की सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल को ध्यान में रखते हुए अलबेलापारा कांकेर के इस सामान्य बालिका छात्रावास के लिए नवीन भवन की यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए और उचित आदेश जारी किए जाएं। छात्राओं ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस बार उनकी इस जायज और संवेदनशील मांग पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेगा। इस दौरान छात्रावास की कई छात्राएं मुख्य रूप से उपस्थित रहीं।

साक्षरता से बदल रही पुनर्वासित युवाओं की जिंदगी, उल्लास साक्षरता केंद्र का छठवां बैच शुरू, 90 युवाओं को मिलेगा पढ़ने-लिखने का प्रशिक्षण

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशिष पदमवार। शिक्षा की रोशनी अब उन युवाओं तक भी पहुंच रही है, जिन्हें कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला और जो अब तक पढ़ना-लिखना नहीं सीख पाए थे। जिले में संचालित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पुनर्वास केंद्र बीजापुर में साक्षरता केंद्र के छठवें बैच का शुभारंभ किया गया। इस बैच में 90 असाक्षर पुनर्वासित युवाओं को बुनियादी साक्षरता और अंकज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।कलेक्टर विश्वदीप के मार्गदर्शन में संचालित इस पहल का उद्देश्य पुनर्वासित युवाओं को शिक्षा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। जिला प्रशासन का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में लौट रहे युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उल्लास साक्षरता अभियान के परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। हाल ही में कोण्डापल्ली में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे एक पुनर्वासित दंपति ने बताया कि पुनर्वास केंद्र में मिली साक्षरता और अंकज्ञान ने उनके जीवन को नई दिशा दी है। उन्होंने बताया कि आज वे पढ़ना-लिखना सीखने के बाद सफलतापूर्वक दुकान का संचालन कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान शिक्षार्थियों को उल्लास प्रवेशिका, मार्गदर्शिका, अभ्यास पुस्तिका, पेन सहित अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। अध्ययन सामग्री मिलने पर पुनर्वासित युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया।जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के जिला परियोजना अधिकारी कमलदास झाड़ी ने गोंडी बोली में शिक्षा का महत्व बताते हुए शिक्षार्थियों को नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करती है। कार्यक्रम में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

बादी नार तालाब गहरीकरण कार्यस्थल पर श्रमिकों को अधिकारों, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण की दी गई जानकारी

मनरेगा कार्यस्थल से स्वच्छता और जनजागरूकता का संदेश, प्लास्टिक हटाओ स्वच्छ गांव बनाओ अभियान को मिला जनसमर्थन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती प्रेमलता पद्माकर के मार्गदर्शन में जिलेभर में विकास, रोजगार, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद पंचायत साजा अंतर्गत ग्राम पंचायत तेंदुआ में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों एवं मनरेगा श्रमिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं, स्वच्छता प्रबंधन तथा उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। अभियान के तहत मनरेगा योजना अंतर्गत गांव के अंतिम छोर पर स्थित बादी नार तालाब गहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। कार्यस्थल पर पहुंचे जिला समन्वयक ने श्रमिकों से संवाद करते हुए उन्हें श्रमिक अधिकारों, रोजगार संबंधी प्रावधानों तथा देश के विभिन्न कानूनों एवं न्यायिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान श्रमिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में ग्रामीणों एवं श्रमिकों को नवीन स्वच्छता प्रावधानों तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीणों को बताया गया कि कचरे का उचित पृथक्करण और वैज्ञानिक प्रबंधन स्वच्छ एवं स्वस्थ ग्राम निर्माण की आधारशिला है। उन्हें गीला कचरा, सूखा कचरा, सेनेटरी कचरा एवं विशेष देखभाल (डोमेस्टिक हैजार्डस) कचरा को अलग-अलग संग्रहित एवं निपटान करने की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही घर-घर कचरा पृथक्करण, कम्पोस्ट निर्माण, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) तथा संसाधनों के पुनः उपयोग के लाभों पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर जिले में संचालित ÷प्लास्टिक हटाओङ्कस्वच्छ गांव बनाओ÷ विशेष अभियान की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। उन्हें प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह त्यागने, कपड़े एवं जूट के थैलों का उपयोग बढ़ाने तथा पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। पंचायत स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था के संचालन हेतु यूजर चार्ज के महत्व एवं सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान आवास दिवस एवं रोजगार दिवस का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के ऐसे हितग्राहियों, जिनके आवास निर्माण कार्य अपूर्ण हैं, उन्हें शीघ्र निर्माण पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही ग्रामीणों से जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए प्रत्येक घर में सोखता गड्ढा निर्माण एवं वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली विकसित करने की अपील की गई, ताकि भूजल स्तर में सुधार हो और गांवों में जलभराव एवं कीचड़ की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रचार-प्रसार हेतु जनजागरूकता गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से भी ग्रामीणों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त ग्राम और सतत विकास के महत्व से अवगत कराया गया। अभियान के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों, रोजगार सहायकों, स्वच्छता दीदियों, स्व-सहायता समूहों, युवा मंडलों, मनरेगा श्रमिकों एवं ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। सभी ने सामूहिक रूप से अपने गांव को स्वच्छ, सुंदर, प्लास्टिक मुक्त, जल-संरक्षित एवं आत्मनिर्भर ग्राम बनाने का संकल्प लिया। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वच्छता, कचरा पृथक्करण, प्लास्टिक उन्मूलन एवं जल संरक्षण जैसे जनहितकारी अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाकर स्वस्थ, स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल बेमेतरा के निर्माण में अपना योगदान दें।

प्रकृति प्रेमी एवं समाजसेवी विंध्येश्वरशरण सिंहदेव (विंकी बाबा) ऐतिहासिक मंच हुए से सम्मानित..!

साउथ एशिया जनसरोकार सम्मान के साथ द एक्टिविस्ट नेशनल अवार्ड 2026 से नवाजे गए

अम्बिकापुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी अंबिकापुर में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मान समारोह में समाजसेवा, जनसरोकार और मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सरगांव पैलेस के संचालक एवं प्रकृति प्रेमी समाजसेवी श्री विंध्येश्वरशरण सिंहदेव (विंकी बाबा) को प्रतिष्ठित ÷साउथ एशिया जनसरोकार सम्मान 2026÷ एवं ÷द एक्टिविस्ट नेशनल अवार्ड 2026÷ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें समाजहित, जनसेवा, पर्यावरण संरक्षण तथा मानवीय संवेदनाओं को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए सतत एवं प्रेरणादायी कार्यों के लिए प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों से आए पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया।विंकी बाबा अपनी सादगी, सहज व्यवहार और जनकल्याणकारी सोच के लिए सरगुजा संभाग सहित पूरे क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं। वर्षों से वे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सक्रिय रहकर सहयोग, सेवा और सकारात्मक संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देते आ रहे हैं। उनके कार्यों में प्रकृति संरक्षण, सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्यों के प्रति विशेष प्रतिबद्धता दिखाई देती है।कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कुछ व्यक्तित्व केवल अपना जीवन नहीं जीते, बल्कि अपने कार्यों से समाज को नई दिशा और प्रेरणा भी देते हैं। विंध्येश्वरशरण सिंहदेव ऐसे ही व्यक्तित्व हैं, जिनका जीवन समाज सेवा, संवेदनशीलता और जनहित के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपने व्यवहार और कार्यों के माध्यम से लोगों के बीच विश्वास, सहयोग और सकारात्मक सोच का वातावरण निर्मित किया है।÷जन सरोकार÷ एवं ÷द एक्टिविस्ट÷ परिवार द्वारा आयोजित यह सम्मान समारोह उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को समर्पित था, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मिसाल कायम की है। विंकी बाबा का इस सम्मान के लिए चयन पूरे सरगुजा-अंबिकापुर क्षेत्र के लिए गर्व और सम्मान का विषय माना जा रहा है।30 एवं 31 मई 2026 को माता राजमोहनी भवन, अंबिकापुर में आयोजित इस भव्य आयोजन में पत्रकारिता, सामाजिक सरोकार, जनजागरण और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा-परिचर्चा भी हुई। देश के दर्जनों राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने जनसरोकार और सामाजिक परिवर्तन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए आयोजन को ऐतिहासिक बताया।

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं 50 आवेदन प्राप्त

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टरेट में जनदर्शन का आयोजन किया गया। जनदर्शन में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। जनदर्शन के दौरान नागरिकों ने अपनी विभिन्न मांगों, शिकायतों एवं समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दूरभाष पर एवं समक्ष बुलाकर प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कई प्रकरणों का समाधान मौके पर ही किया गया।आज आयोजित जनदर्शन में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए। तात्कालिक महत्व के मामलों का प्राथमिकता से निराकरण किया गया, जबकि गंभीर एवं जांच योग्य

आवेदनों को समय-सीमा (टीएल) पंजी में दर्ज कर नियमानुसार शीघ्र निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जनदर्शन में निराश्रित एवं वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बैटरी चालित ट्रायसायकल, प्रधानमंत्री आवास योजना, कटा हुआ रकबा जोड़ने, खाद गड्ढा हटाने, आम रास्ता खुलवाने सहित अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों को उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।इस अवसर जनप्रतिनिधि व ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

पूर्व खाद्य अधिकारी और पंचायत सचिव पर अवैध रेत कारोबार का आरोप

जकांछ (जे) जिलाध्यक्ष विजय झाड़ी ने की जांच की मांग, कहा– कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। जिले में अवैध रेत उत्खनन को लेकर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के जिलाध्यक्ष विजय झाड़ी ने पूर्व खाद्य अधिकारी बी.एल. पदमाकर और ग्राम पंचायत सचिव सीताराम मोरला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों की कथित मिलीभगत से तारलागुड़ा, चेंदुर और कोत्तूर क्षेत्र में अवैध रेत का कारोबार चल रहा है।जारी प्रेस विज्ञप्ति में झाड़ी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों की रेत खदानों से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन कर रेत का भंडारण किया जा रहा है। इसके बाद रेत को तेलंगाना और महाराष्ट्र तक भेजकर बेचा जा रहा है। उनका कहना है कि इससे शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है और पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंच रही है।विजय झाड़ी ने कहा कि जिले के प्राकृतिक संसाधनों की लगातार लूट हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में रेत माफिया सक्रिय हैं और प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायतों में अनियमितताओं के आरोप झेल चुके लोगों की संलिप्तता से यह पूरा नेटवर्क और मजबूत हुआ है। झाड़ी ने कहा कि इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बार-बार शिकायतें और खबरें सामने आ रही हैं तो जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उनका कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिलाध्यक्ष ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि तारलागुड़ा, चेंदुर और कोत्तूर क्षेत्र में चल रहे कथित अवैध रेत उत्खनन, भंडारण और परिवहन की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) जिलेभर में आंदोलन शुरू करेगी।

जकांछ (जे) की प्रमुख मांगें

तारलागुड़ा, चेंदुर और कोत्तूर क्षेत्र में रेत उत्खनन की जांच कराई जाए।
अवैध रेत भंडारण और परिवहन पर तत्काल रोक लगाई जाए।
तेलंगाना और महाराष्ट्र की ओर जाने वाले रेत वाहनों की जांच की जाए।
राजस्व नुकसान और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कराया जाए।
दोषियों के खिलाफसख्त कार्रवाई की जाए।
कार्रवाई नहीं होने पर जिलेभर में आंदोलन किया जाएगा।

शिवनाथ नदी क्षेत्र में खनिज विभाग की सतत निगरानी, नियमानुसार पूरी की जा रही रेत खदान संचालन की प्रक्रिया

बेमेतरा/मूक पत्रिका

ग्राम बहेरघट स्थित शिवनाथ नदी की रेत खदान के संबंध में प्रकाशित समाचार के परिप्रेक्ष्य में खनिज विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि रेत खदान के आवंटन एवं संचालन की समस्त प्रक्रियाएं नियमानुसार संचालित की जा रही हैं तथा क्षेत्र की नियमित निगरानी की जा रही है। खनिज विभाग के अनुसार ग्राम बहेरघट, तहसील बेरला स्थित रेत खदान की ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत श्री प्रतीक सिंह राजपूत को अधिमानी बोलीदाता घोषित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार आशय पत्र जारी किया जा चुका है। वर्तमान में पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात खनिज विकास एवं उत्पादन समझौते सहित अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर कार्यानुमति प्रदान की जाएगी। प्राप्त आवेदन एवं जनसूचनाओं के आधार पर खनिज विभाग द्वारा दिनांक 25 मई 2026 को संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्थल का अवलोकन कर आवश्यक जानकारी संकलित की गई तथा पंचनामा तैयार किया गया। विभाग द्वारा क्षेत्र की गतिविधियों पर सतत नजर रखी जा रही है तथा खनिज संसाधनों के संरक्षण एवं नियमों के प्रभावी पालन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। खनिज विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खनिजों के अवैध उत्खनन अथवा परिवहन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल विभाग को सूचित करें, जिससे आवश्यक जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को

बेमेतरा/मूक पत्रिका

आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय में 20 जून 2026 (शनिवार) तक जमा कर सकेंगे। इसके बाद विद्यालय प्रमुख द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण कर उन्हें 22 जून 2026 (सोमवार) तक विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजा जाएगा। विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त आवेदनों की सूची सहित आवेदन 24 जून 2026 (बुधवार) तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा किए जाएंगे।कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन 05 जुलाई 2026 (रविवार) को किया जाएगा। परीक्षा का समय दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

पात्रता एवं चयन मापदण्ड- योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए और उसके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। विद्यार्थी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। साथ ही कक्षा 4वीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो। अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कांकेर में गरमाया मुद्दा: ग्राम सभा ने पेसा कानून के तहत 14 धर्मांतरित व्यक्तियों के ञ्ज सर्टिफिकेट निरस्त करने की मांग की, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, अंतागढ़ के बड़े तेवड़ा में ग्राम सभा का बड़ा फैसला

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ :-कांकेर, 08 जून 2026: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां ग्राम बड़े तेवड़ा की ग्राम सभा ने भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा एक्ट) तथा छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 के तहत एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया है। इस संकल्प के आधार पर ग्राम के 14 व्यक्तियों के अनुसूचित जनजाति (गोंड) प्रमाण पत्रों की जांच और उन्हें निरस्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कांकेर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम सभा का आरोप है कि इन व्यक्तियों ने गोंड समाज की पारंपरिक संस्कृति, पेन पूजा, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार और सामाजिक पर्वों (पंडुम) समेत अन्य पारंपरिक रीति-रिवाजों का परित्याग कर एक पृथक धार्मिक व्यवस्था को अपना लिया है, जिसके कारण उनका अनुसूचित जनजाति का दर्जा समाप्त किया जाना चाहिए। ग्राम सभा ने इस विषय को आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न मानते हुए प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सभा द्वारा बीते महीने यानी 18 मई 2026 को एक विशेष बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। ग्राम सभा के प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले साल दिसंबर महीने से ग्राम बड़े तेवड़ा और आसपास के क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की संगठित गतिविधियों और शव दफनाने से जुड़े विवादों के बाद से ग्रामीणों में एक व्यापक जागरूकता आई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बाहरी मिशनरियों और धर्मांतरण की गतिविधियों के कारण गांव की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीणों ने अवैध धर्मांतरण, अवैध चर्चों और आदिवासी संस्कृति पर पड़ रहे प्रभावों के विरुद्ध संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है। इस संबंध में धर्मांतरण विरोधी अभियान में सक्रिय ईश्वर कावड़े ने बताया कि यह लड़ाई आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा का संघर्ष है। उनका कहना है जो लोग ईसाई रीति-नीति का पालन कर रहे हैं, वे आदिवासी पहचान और अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने बस्तर सहित समस्त अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं से संविधान, पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून के तहत प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक होने की अपील की है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी मूल पहचान से वंचित न होना पड़े। हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से स्पष्ट किया है कि ग्राम सभा का यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष के विरोध में नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य केवल आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच एवं विधि सम्मत कार्रवाई की अपेक्षा व्यक्त की है। इस संबंध में कानूनी पक्ष को प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता मनीष जैन ने बताया कि ग्राम सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 342, पांचवीं अनुसूची, पेसा एक्ट 1996 और छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपना प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा ने स्वयं कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है, बल्कि सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कानून के अनुसार जांच की मांग की है। अब जिला प्रशासन इस प्रस्ताव और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करेगा, जिसके बाद इस प्रकरण को सक्षम जाति सत्यापन प्राधिकारी या उच्च स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष भेजा जा सकता है, जहां सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा कानून अपने हाथ में लेने के बजाय इस संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुसरण करना विधि के शासन में उनके विश्वास को दर्शाता है। फिलहाल ग्राम सभा के प्रतिनिधियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन से त्वरित जांच और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

अनियमितता पर विक्रय प्रतिबंध, लाइसेंस निलंबन एवं उर्वरक जब्ती की कार्रवाई; जमाखोरी और कालाबाजारी पर होगी एफआईआर

खरीफ सीजन 2026 : किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने प्रशासन सख्त, 132 केंद्रों का निरीक्षण, 19 विक्रेताओं को नोटिस

बेमेतरा/मूक पत्रिका

खरीफ सीजन 2026 के दौरान जिले के किसानों को निर्धारित मूल्य पर, समय पर एवं उच्च गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी गंभीरता एवं सख्ती के साथ कार्य कर रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा के निर्देशानुसार जिले में गठित जिला स्तरीय उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वाड) टीम एवं कृषि विभाग द्वारा लगातार मैदानी स्तर पर सघन निरीक्षण एवं निगरानी की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उड़नदस्ता एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अब तक जिले के 132 निजी एवं सहकारी कृषि केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान स्टॉक संधारण में अनियमितता, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने तथा उर्वरक नियंत्रण संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामले पाए जाने पर 19 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अवैध भंडारण एवं नियमों की अवहेलना पाए जाने पर एक विक्रय केंद्र से यूरिया उर्वरक जब्त किया गया है। वहीं गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 4 विक्रय केंद्रों पर तत्काल प्रभाव से विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है तथा 1 कृषि केंद्र का लाइसेंस निलंबित किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। यदि कोई भी निजी कृषि केंद्र या सहकारी समिति निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद विक्रय करते, जमाखोरी करते अथवा अमानक उर्वरकों का व्यापार करते पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध सीधे पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। किसानों से प्राप्त शिकायतों एवं गोपनीय सूचनाओं पर बिना पूर्व सूचना के तत्काल छापेमारी की जाएगी।

जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण, किसानों से वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग की अपील-कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा जिले के लिए 68,300 मीट्रिक टन उर्वरक भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 48,569 मीट्रिक टन उर्वरक जिले को प्राप्त हो चुका है, जो गत वर्ष के कुल उर्वरक वितरण का लगभग 75 प्रतिशत है। प्राप्त उर्वरकों में से 30,341 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 44 प्रतिशत है। डीएपी उर्वरक के संबंध में विभाग ने बताया कि 16,200 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 5,165 मीट्रिक टन डीएपी का भंडारण सहकारी समितियों एवं विक्रय केंद्रों में किया जा चुका है। यह मात्रा गत वर्ष हुए डीएपी वितरण की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत है। डीएपी के अतिरिक्त जिले को अब तक 7,901 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) तथा 6,279 मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक प्राप्त हो चुका है। सिंगल सुपर फास्फेट की उपलब्धता लक्ष्य के विरुद्ध 143 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जिससे जिले में फास्फेटिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है।

सिंगल सुपर फास्फेट एवं एनपीके उपयोगी विकल्प-कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) में लगभग 16 प्रतिशत फास्फोरस एवं 11 प्रतिशत सल्फर पाया जाता है, जो फसलों की वृद्धि एवं उत्पादन के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसलिए किसान भाई डीएपी की उपलब्धता पर निर्भर रहने के बजाय सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) एवं एनपीके उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे फसलों को आवश्यक पोषक तत्व संतुलित रूप से प्राप्त होंगे तथा उर्वरकों की मांग का दबाव भी कम होगा।

किसानों से अपील-जिला प्रशासन ने जिले के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि उर्वरक खरीदते समय विक्रेता से अनिवार्य रूप से पक्का बिल प्राप्त करें। यदि कोई दुकानदार निर्धारित दर से अधिक राशि की मांग करता है, खाद की कृत्रिम कमी बताकर जमाखोरी करता है अथवा किसी प्रकार की अनियमितता करता है, तो इसकी सूचना तत्काल अपने निकटतम कृषि अधिकारी या उड़नदस्ता टीम को दें। प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा एवं उन्हें समय पर गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उड़नदस्ता टीम में डॉ. श्याम लाल साहू (उर्वरक निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी), दिनेश कुमार धुर्वे, देवानंद देवांगन, राकेश कुमार चतुर्वेदी, दीपक कुमार साहू तथा कुलेश्वर सिन्हा सहित कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं, जो जिलेभर में सतत निगरानी एवं निरीक्षण की कार्रवाई कर रहे हैं।

संपादकीय

अग्निकांड- मौत के बाद जांच, जांच के बाद खामोशी

राजधानी दिल्ली में एक इमारत में आग लगने की वजह से इक्कीस लोगों की जान चली गई। उसके अगले ही दिन बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में आग लग गई, जिसमें पांच लोगों के मरने की खबरें आईं।किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक यह होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं, ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। मगर ऐसा लगता है कि आए दिन इमारतों में आग लगने और उसमें लोगों की जान जाने की घटनाओं से कोई सबक नहीं लेने की लापरवाही एक सामान्य चलन बन चुकी है।राजधानी दिल्ली में एक इमारत में आग लगने की वजह से इक्कीस लोगों की जान चली गई। उसके अगले ही दिन बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिसमें पांच लोगों के मरने की खबरें आईं। इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवस्थागत कमियों की कलई खोल दी है।आमतौर पर किसी भी अस्पताल में मरीज इस उम्मीद में इलाज कराने जाते हैं, ताकि उनकी जिंदगी बच सके। मगर जब वहां अति सुरक्षित माने जाने वाले कक्ष में ही उनकी जान पर बन आए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अस्पतालों में सुरक्षा नियमों की जिस तरह अनदेखी हो रही है, उससे स्पष्ट है कि चिकित्सा एक ऐसे व्यवसाय का रूप ले चुकी है, जहां शायद जिंदगी की कोई कीमत नहीं।पिछले कुछ वर्षों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों में बार-बार गंभीर खामियां पाई गई हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। मुजफ्फरपुर में हुए हादसे ने साफ कर दिया है कि अस्पताल में किस हद तक घोर लापरवाही बरती जा रही थी।मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का पांच सदस्यीय दल बनाया गया है। अब जांच की रिपोर्ट कब आएगी, उस पर क्या कार्रवाई होगी, यह आम लोगों को शायद ही पता चले। मगर इस घटना में मारे गए मरीज कभी घर नहीं लौटेंगे।बेहतर होता कि स्वास्थ्य विभाग संबंधित अस्पताल से तत्काल जवाब-तलब करता कि मरीजों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन निकास की व्यवस्था के साथ अग्निरोधक उपाय उसने पहले क्यों नहीं किए। हैरत की बात है कि अस्पताल परिसरों में शॉर्ट सर्किट जैसी समस्या से निपटने को लेकर एहतियात बरतना और बुनियादी इंतजाम करना जरूरी नहीं समझा जाता है। जांच और राहत के आश्वासनों से इतर सवाल यह है कि इस तरह की व्यापक लापरवाही के लिए प्रशासन की अनदेखी की जवाबदेही कब तय की जाएगी!

किसी भी राज्य के विकास के लिए स्पष्ट विजन का होना जरूरी है। ऐसा न हो तो संसाधन बिखरते हैं, ऊर्जा का सही उपयोग नहीं पाता और लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। 2017 में जब एक भगवादारी संन्यासी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, कारपोरेट जगत से लेकर सभी लोगों के मन में एक ही प्रश्न था कि क्या वह राज्य को विकास की राह पर ले जा पाएंगे? ऐसा राज्य जहां माफिया और अपराधियों की तूती बोलती हो, निवेशक आने से घबराते हों और जिसकी पहचान बीमारू के रूप में होती हो। लोगों के मन में यह प्रश्न उठना सहज ही था, क्योंकि प्रबंधन के स्तर पर राज्य की चूलें हिली हुई थीं। लोगों के प्रश्नों का जवाब उचित प्रबंधन ही दे सकता था और उसके बाद से अब तक का समय यदि इसकी मिसाल बना तो इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट विजन ही था।

मैनेजमेंट गुरु योगी आदित्यनाथ

(प्रो. दीप्ति तनेजा)

किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? यह एक गंभीर सवाल है और लोग इसका जवाब अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग ही देंगे। लेकिन, संदर्भ उत्तर प्रदेश का हो तो इसका सही जवाब है-विजन। किसी भी राज्य के विकास के लिए स्पष्ट विजन का होना जरूरी है। ऐसा न हो तो संसाधन बिखरते हैं, ऊर्जा का सही उपयोग नहीं पाता और लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। 2017 में जब एक भगवादारी संन्यासी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, कारपोरेट जगत से लेकर सभी लोगों के मन में एक ही प्रश्न था कि क्या वह राज्य को विकास की राह पर ले जा पाएंगे? ऐसा राज्य जहां माफिया और अपराधियों की तूती बोलती हो, निवेशक आने से घबराते हों और जिसकी पहचान बीमारू के रूप में होती हो। लोगों के मन में यह प्रश्न उठना सहज ही था, क्योंकि प्रबंधन के स्तर पर राज्य की चूलें हिली हुई थीं। लोगों के प्रश्नों का जवाब उचित प्रबंधन ही दे सकता था और उसके बाद से अब तक का समय यदि इसकी मिसाल बना तो इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट विजन ही था।

विजन का सही एग्जिक्यूशन- कारपोरेट जगत में एक वाक्य बहुत कॉमन है- 'मैनेजर काम सही करता है, लीडर सही काम कराता है।' यह योगी आदित्यनाथ की प्रबंधकीय दृष्टि ही थी कि उन्होंने सबसे पहले सही काम तय किए और इसे सही तरीके से करने की जिद पकड़ी। मूल सिद्धांत यह कि कानून का राज ही विकास की राह है। यह उनका एक रणनीतिक घोषणापत्र था, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को एक दिशा दी, एक उद्देश्य दिया। साथ ही एक कसौटी भी रखी जिसमें हर नीति, हर निर्णय और हर अधिकारी को परखा जा सके। विजन में ऐसी स्पष्टता हो तो एग्जिक्यूशन की धार अपने आप तेज हो जाती है। बीते नौ सालों में समावेशी विकास की महागाथा, विश्वस्तरीय आयोजन और 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, यह विजन के सही एग्जिक्यूशन से ही आए। इसीलिए योगी आज एक ऐसे मैनेजमेंट गुरु के रूप में देखे जा रहे हैं, जिनके फैसले केस स्टडी के रूप में प्रबंधकीय संस्थानों और छात्रों के लिए रुचि का विषय हैं।

जीरो टॉलरेंस बना ब्रांड पोजीशनिंग टूल- योगी सरकार का लक्ष्य था कि बीमार पड़े राज्य को पुनर्जीवित किया जाए। कारपोरेट जगत में इस प्रक्रिया को 'टर्नअराउंड' कहते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। पुरानी जड़ें उखाड़ने से लेकर पुराने प्रशासनिक ढांचे तोड़ने थे। उन लोगों को भी बदलना था, जो वर्षों से 'यही होता आया है' की मानसिकता में जी रहे थे। 2017 के पहले की स्थिति ऐसी ही थी, जिसमें पूरा तंत्र जड़ हो चुका था। न कोई जवाबदेही थी और न ही कोई संस्कृति। उत्तर प्रदेश की पहचान 'दंगा प्रदेश' के रूप में थी और यह केवल एक छवि नहीं थी, यह अभिशाप था जो युवाओं को पलायन के लिए बाध्य कर रहा था तो उद्यमियों को आने से रोक रहा था। ऐसे में राज्य की अलग पहचान तभी हो सकती थी जब पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर राज्य को ब्रांड बनाया जाए।

विजन में ऐसी स्पष्टता हो तो एग्जिक्यूशन की धार अपने आप तेज हो जाती है। बीते नौ सालों में समावेशी विकास की महागाथा, विश्वस्तरीय आयोजन और 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, यह विजन के सही एग्जिक्यूशन से ही आए।

इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति को एक 'ब्रांड पोजीशनिंग टूल' के रूप में इस्तेमाल किया। बुलडोजर ने अपराधियों के हौसले तोड़े तो माफिया के खिलाफ अभियान ने सीधा संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। पूरी कठोरता से इस फैसले के क्रियान्वयन ने देश के उद्योग जगत को स्पष्ट 'मार्केटिंग सिग्नल' दिया कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। परिणाम राजस्व की बड़ी उछाल के रूप में सामने आया और आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है तो यह यहां के प्रबंधन मॉडल की सफलता का परिणाम है।

कुशल सीईओ जैसी कार्यशैली- प्रबंधन में विजन और ब्रांडिंग से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है- एग्जिक्यूशन। व्यक्तिगत निगरानी और समय-सीमा के प्रति अटल प्रतिबद्धता। हर परियोजना की डेली मॉनीटरिंग, डैशबोर्ड रिव्यू और स्वयं मुख्यमंत्री की देर रात तक चलने वाली समीक्षा बैठकें, यह किसी स्टार्टअप के कुशल व मेहनती 'सीईओ' की कार्यशैली नजर आती है। जब सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति खुद जवाबदेह हो, तो पूरा सिस्टम उत्तरदायी हो जाता है। 2025 का महाकुंभ इस एग्जिक्यूशन की क्षमता का सबसे बड़ा और सबसे दृश्यमान प्रमाण था। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का एक स्थान पर आना, मानव इतिहास का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और भीड़ प्रबंधन का प्रयोग था। परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, डिजिटल सेवाएं, हर विभाग को एक साथ-एक लय में चलाना, यह तब ही संभव है जब 'सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल' व्यवहार में जीवित हो। महाकुंभ की सफलता ने प्रबंधन का ऐसा इतिहास लिखा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी दौड़े चले आए।

ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी- एक और पहलू है जिसे अनदेखा करना असंभव है- 'ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी।' इस स्ट्रेटजी में आप प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर एक नया और अछूता बाजार बनाते हैं, जहां कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। जब सभी राज्य एक ही तरह की नीतियां अपना रहे थे, उत्तर प्रदेश ने 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) और बाद में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन कुज़ीन' (ओडीओसी) जैसे नवाचार किए। ओडीओपी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा आधार बन गया। इस नीति ने लाखों कारीगरों को न केवल आजीविका दी, बल्कि उन्हें एक पहचान भी दी और यही किसी भी सफल संगठन की 'एचआर पॉलिसी' का सार होता है।

शोध का विषय बना यूपी मॉडल

किसी भी गंभीर संकट में प्रबंधन की असली परीक्षा होती है। उत्तर प्रदेश ने कोविड लहर में यह परीक्षा दो बार दी। ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य ढांचे की सीमाएं और लाखों जिंदगियों की जिम्मेदारी, इन सबके बीच जो प्रशासनिक प्रतिक्रिया सामने आई, वह 'इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर' के रूप में थी। जिला स्तर पर निगरानी, ऑक्सीजन वितरण की रियल-टाइम ट्रैकिंग, दवाओं की उपलब्धता, यह सब उसी 'डैशबोर्ड गवर्नेंस' का विस्तार था जो इस सरकार की पहचान बन चुका है। उत्तर प्रदेश का बदलाव प्रबंधन की बड़ी कहानी है और इसीलिए आज आईआईएम के शोधार्थी 'यूपी मॉडल' पर शोधपत्र लिख रहे हैं और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। यह किसी राज्य के लिए सामान्य बात नहीं है। भगवा कपड़ों में एक संन्यासी का सीईओ रूप सभी को प्रभावित कर रहा है। योगी ने सिद्ध किया है कि नेतृत्व की कोई पोशाक नहीं होती और न ही इसके मूल में कोई पृष्ठभूमि होती है। जनता के प्रति प्रतिबद्धता निष्कपट हो, तो मठ से निकला एक संन्यासी भी देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य का सबसे सफल 'टर्नअराउंड सीईओ' बन सकता है। (लेखिका अर्थशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रो. हैं।)

ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

जीवन का आधार है पर्यावरण

(रमेश सर्राफ धमोरा)

पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है हमारे आसपास या हमारे चारों और। आवरण का अर्थ होता है हम चारों और जिससे घिरे हैं। अर्थात पर्यावरण का अर्थ हमारे आस-पास के वातावरण से हैं। पर्यावरण पेड़-पौधों, वायु हमारे आस-पास की सभी चीजों से मिलकर बनता है।

दुनिया में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को कई कार्यक्रमों के जरिये प्रकृति को संरक्षित रखने और इससे खिलवाड़ न करने के लिए जागरूक किया जाता हैं। इन कार्यक्रमों के जरिये लोगों को पेड़-पौधे लगाने, पेड़ों को संरक्षित करने, हरे पेड़ न काटने, नदियों को साफ रखने और प्रकृति से खिलवाड़ न करने जैसी चीजों के लिए जागरुक किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस एक अभियान है। इस अभियान की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य वातावरण की स्थितियों पर ध्यान केन्द्रित करने और पृथ्वी के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव का भाग बनने के लिए लोगों को प्रेरित करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। लेकिन विश्व स्तर पर इसके मनाने की शुरुआत 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। जहां 119 देशों की मौजूदगी में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साथ ही प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन भी हुआ था। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम जलवायु के लिए अभी है। यह थीम जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता और इसके वास्तविक, ठोस समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करती है।

पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है हमारे आसपास या हमारे चारों और। आवरण का अर्थ होता है हम चारों और जिससे घिरे हैं। अर्थात पर्यावरण का अर्थ हमारे आस-पास के वातावरण से हैं। पर्यावरण पेड़-पौधों, वायु हमारे आस-पास की सभी चीजों से मिलकर बनता है। पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता हैं। मानव और पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जैसे पेड़ों का कम होना,

वायु प्रदूषण आदि मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता हैं। मानव की अच्छी बुरी आदतों का प्रभाव सीधा पर्यावरण पर पड़ता हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को पर्यावरण के प्रति सचेत करना हैं। उसका उद्देश्य पूरी प्रकृति व पर्यावरण की सुरक्षा करना हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट पृथ्वी पर मंडरा रहे तीन बड़े पर्यावरणीय संकटों जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण से निपटने के लिए एक वैज्ञानिक खाका प्रदान करती है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये मानव अस्तित्व के लिए एक स्व-निर्मित खतरा हैं। प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 90 लाख लोग असामयिक रूप से अपनी जान गंवाते हैं। लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। मानवता ने पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक और अस्थिर दोहन किया है जिससे हमारी पृथ्वी की जीवन-समर्थन क्षमता कमजोर हो गई है।

पर्यावरणीय संकट से समाधान की ओर बढ़ने का समय

पर्यावरणीय संकट का मूल कारण विकास की वह अवधारणा है जिसमें प्रकृति को केवल संसाधन और उपभोग की वस्तु मान लिया गया है। हमने जंगलों को उद्योगों के लिए, नदियों को अपशिष्ट के लिए और भूमि को कंक्रीट के जंगलों में बदलने के लिए प्रयोग किया। प्रकृति हमें जीवन का आधार निःशुल्क देती है, लेकिन हमने उसके प्रति कृतज्ञता के बजाय दोहन का व्यवहार अपनाया। परिणामस्वरूप वनस्पतियों का विनाश, वन्य जीवों का संकट, भूमिगत जल का क्षय और प्रदूषण का विस्तार निरंतर बढ़ रहा है।

(ललित गर्ग)

वर्तमान संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संकट भी है। वायु प्रदूषण लाखों लोगों की असामयिक मृत्यु का कारण बन रहा है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य को बचाने का वैश्विक संकल्प है। वर्ष 2026 का विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण, जल संकट, वायु प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी के अस्तित्व को गंभीर चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का अंत (ठमंज च्वेंजपब च्वससनजपवद) केवल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान नहीं है, बल्कि उपभोगवादी जीवनशैली और प्रकृति-विरोधी विकास मॉडल पर पुनर्विचार का भी संदेश है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को झेल रही है। कहीं भीषण गर्मी जीवन को असहनीय बना रही है, कहीं अनियंत्रित वर्षा और बाढ़ तबाही ला रही है, तो कहीं सूखा और जल संकट मानव अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों में आग, हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, महानगरों में प्रदूषण, बेंगलुरु जैसे तकनीकी नगरों में जल संकट और लगातार बढ़ती गर्मी इस बात के संकेत हैं कि पर्यावरणीय संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें चेतावनी दे रही हैं कि पिछले एक दशक में जलवायु संबंधी आपदाओं से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और खरबों डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है। जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण-ये तीनों संकट परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को

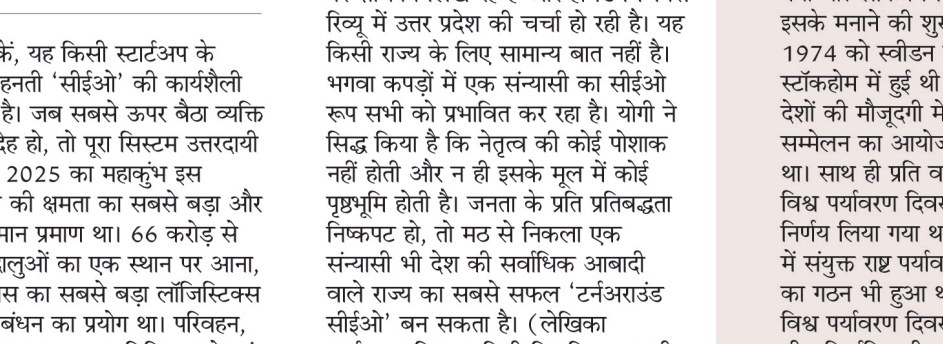

नियंत्रित नहीं किया गया तो मानव सभ्यता के सामने अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता है। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन आज भी दुनिया उस दिशा में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विश्व के सामने उपस्थित इस सबसे बड़े संकट को भारत की राजनीति में वह महत्व नहीं मिला, जिसका वह अधिकारी है। चुनावी घोषणापत्रों में पर्यावरण का उल्लेख तो होता है, लेकिन वह केवल औपचारिकता भर रह जाता है। राजनीतिक दल यह मानकर चलते हैं कि पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन वोट दिलाने वाले मुद्दे नहीं हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रश्न न तो चुनावी बहस का हिस्सा बनते हैं और न ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का। जबकि सच्चाई यह है कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसी प्रश्न पर निर्भर करती है।

पर्यावरणीय संकट का मूल कारण विकास की वह अवधारणा है जिसमें प्रकृति को केवल संसाधन और उपभोग की वस्तु मान लिया गया है। हमने जंगलों को उद्योगों के लिए, नदियों को अपशिष्ट के लिए और भूमि को कंक्रीट के जंगलों में बदलने के लिए प्रयोग किया। प्रकृति हमें जीवन का आधार निःशुल्क देती है, लेकिन हमने उसके प्रति कृतज्ञता के बजाय दोहन का व्यवहार अपनाया। परिणामस्वरूप वनस्पतियों का विनाश, वन्य जीवों का संकट, भूमिगत जल का क्षय और प्रदूषण का विस्तार निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति ने सदैव प्रकृति को पूजनीय माना है। वृक्षों, नदियों, पर्वतों और वनस्पतियों को केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवनदाता के रूप में देखा गया। आयुर्वेद और वनौषधि विज्ञान इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों ने हजारों वर्षों तक मानव स्वास्थ्य की रक्षा की, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में यह ज्ञान और प्राकृतिक संपदा दोनों उपेक्षित होते गए। आज जब नई-नई बीमारियां मानव जीवन को चुनौती दे रही हैं, तब पुनः प्रकृति और वनस्पति जगत की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

वर्तमान संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संकट भी है। वायु प्रदूषण लाखों लोगों की असामयिक मृत्यु का कारण बन रहा है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कभी इंदिरा गांधी ने कहा था कि 'गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है।'

आज यह कथन और अधिक प्रासंगिक हो गया है क्योंकि गरीबी और पर्यावरणीय विनाश एक-दूसरे को बढ़ाने वाले कारक बन गए हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनों की कमी नहीं है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से लेकर अनेक पर्यावरणीय कानून बनाए गए। लेकिन कानूनों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई बनी हुई है। अवैध खनन, वनों की कटाई, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनदेखी और पर्यावरणीय मंजूरियों में शिथिलता इस बात का प्रमाण हैं कि संस्थागत इच्छाशक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी आशा की किरण दिखाई देती है। युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है।

प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज नवागढ़ ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन, समाज को संगठित करने का लिया संकल्प

बेमेतरा/नवागढ़ /मूक पत्रिका

प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज द्वारा नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय स्थित सतनाम भवन में बीते रविवार 07 जून 2026 को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर ब्लॉक, युवा एवं महिला प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष एल.एल. कोसले, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुशीला सोनवानी, प्रदेश महासचिव मोहन बंजारे, प्रदेश सहसचिव दिनेश बंजारे, साहित्य एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एस.आर. बांधे, अश्विनी बबलू त्रिवेंद्र, के.डी. सोनवानी, श्रीमती शकुंतला दांडे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भुवन दास जांगड़े, जिला अध्यक्ष राजा लाल बंजारे, हरिकिशन कुर्रे, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मधु राय सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रमुख पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर आरती भजन के साथ हुआ। सर्वप्रथम सभी पदाधिकारी का पुष्पमाला व गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया तत्पश्चात कार्यक्रम को गति मिला और समाज के कवि एवं साहित्य प्रेमियों को अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ।

संगठन को गांवों तक पहुंचना एवं समाज का सर्वांगीण विकास हमारा प्रथम लक्ष्य – एल एल कोसले –बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एल.एल. कोसले ने नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए समाज द्वारा प्रस्तावित 15 बिंदुओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने सामाजिक एकता, शिक्षा, संगठन और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया।

संगठन की शक्ति को मातृशक्ति को पहचानना जरूरी–सुशीला सोनवानी–कार्यक्रम के दौरान अपने वक्तव्य में संगठन पर जोड़ देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुशीला सोनवानी ने महिलाओं से अधिक से अधिक संख्या में संगठन से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि एकता में ही शक्ति है और संगठित होकर ही समाज अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है।प्रदेश महासचिव मोहन बंजारे ने संस्था की नियमावली एवं समाजहित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के सहयोग से गिरौदपुरी में लगभग ढाई करोड़ रुपये की लागत से भवन का निर्माण किया गया है तथा रायपुर में बहुउद्देशीय भवन निर्माण की योजना पर कार्य चल रहा है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा सतनाम संस्कृति के अनुरूप जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया।

सतनाम संस्कृति हमारी अमूल्य विरासत और गौरव – एस. आर. बांधे–साहित्य एवं संस्कृति समिति के प्रदेश अध्यक्ष एस.आर. बांधे ने कहा कि सतनाम संस्कृति हमारी अमूल्य विरासत और गौरव है, जिसे संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

सामाजिक विकास के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक – श्रीमती मधु राय–जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मधु राय ने समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सामाजिक विकास के कार्यों में सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एल.एल. कोसले ने नवागढ़ ब्लॉक की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें लोचन प्रकाश कौशल को ब्लॉक अध्यक्ष, कमलेश कुमार कोसले, चंद्रभान बघेल, अनुज राम कुर्रे एवं श्रीमती किरण बारले को उपाध्यक्ष, सुनील भारद्वाज को सचिव तथा शिवम टंडन, तेजराम कुर्रे और सीताराम अदिल को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। युवा प्रकोष्ठ में नारायण घृतलहरे को अध्यक्ष तथा रवि कुमार जोशी एवं रोशन जांगड़े को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गई। महिला प्रकोष्ठ में श्रीमती हिमेश्वरी जांगड़े को अध्यक्ष तथा श्रीमती पार्वती पात्रे, पांचबाई जांगड़े और शैलबाई भारती को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। नव-नियुक्त पदाधिकारियों ने समाजहित में सक्रिय रूप से कार्य करने तथा नवागढ़ ब्लॉक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। संगठन विस्तार चुनाव को लेकर बेमेतरा जिला अध्यक्ष राजा लाल बंजारे एवं उनकी टीम ने अथक प्रयास कर कार्यक्रम के लिए क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जिसके लिए भी प्रदेश नेतृत्व ने उनकी सराहना की और सफल कार्यक्रम के लिए बधाई दी।

राम मंदिर चबूतरे पर तलवार से खूनी हमला : कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा, आर्म्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई

रायगढ़/मूक पत्रिका

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस ने राम मंदिर करमकांड चबूतरा के पास हुई मारपीट की घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विधि से संघर्षरत बालक सहित तीन युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

राम मंदिर करमकांड चबूतरा के पास तलवार से हमला कर दो युवकों को किया घायल–प्रार्थी बैकुंठपुर रायगढ़ निवासी दिलीप कुमार चौबे (54 वर्ष) द्वारा थाना कोतवाली रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ड्राइवरी का काम करता है दिनांक 05 जून 2026 की रात करीब 12:30 बजे कोरबा से रायगढ़ लौटने के बाद वह अपने मित्र गौतम सिंह के साथ राम मंदिर करमकांड चबूतरा में बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान रात करीब 3:00 बजे भावेश निषाद उर्फ बिट्टु अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए अपने पास रखी लोहे की तलवार से प्रार्थी के दाहिने पैर तथा गौतम सिंह के बाएं हाथ पर हमला कर चोट पहुंचाई। मारपीट के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गए। थाना कोतवाली रायगढ़ में दिनांक 05.06.2026 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 297/2026 धारा 296, 118(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

धांगरडीपा में दबिश देकर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार–घटना की गंभीरता एवं आरोपियों की गुंडागर्दी को देखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल ने पुलिस टीम के साथ धांगरडीपा क्षेत्र में देर रात दबिश देकर आरोपी भावेश निषाद उर्फ बिट्टु, विशाल यादव, साई यादव एवं एक विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा में लिया। पूछताछ एवं विवेचना के दौरान आरोपियों द्वारा स्कूटी का उपयोग और तलवार से हमला किए जाने की पुष्टि होने पर प्रकरण में आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 जोड़ी गई। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर सभी आरोपियों को दिनांक 06 जून 2026 को गिरफ्तार/अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में पेश किया गया।

चरखापारा मवेशी बाजार पर उठे गंभीर सवाल: तस्कर सक्रिय, चौकी प्रभारी की भूमिका पर संदेह, जिम्मेदार कौन?

धर्मजयगढ़/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत चरखापारा में शुरू हुए मवेशी बाजार को लेकर क्षेत्र में एक बार फिर पशु तस्करी की आशंकाएं तेज हो गई हैं। आरोप है कि बाजार में बड़ी संख्या में बाहरी व्यापारी पहुंच रहे हैं और मवेशियों की खरीद-फरोख्त बिना किसी प्रभावी निगरानी के हो रही है। जिले में पशु तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाए जाने के बावजूद बाजार का संचालन प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार में आने-जाने वाले मवेशियों की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और परिवहन व्यवस्था की निगरानी पर्याप्त रूप से नहीं हो रही है। आरोप है कि इसी ढिलाई का फायदा उठाकर तस्कर सक्रिय हो रहे हैं और मवेशियों को दूसरे क्षेत्रों की ओर भेजा जा रहा है। मामले में सबसे अधिक चर्चा चौकी प्रभारी की भूमिका को लेकर हो रही है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि जब बाजार में गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं तो निगरानी और कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर बाजार में होने वाली खरीद-फरोख्त, परिवहन और प्रशासनिक निगरानी की समीक्षा करने की मांग की है, ताकि पशु तस्करी की आशंकाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। आरोप है कि चरखापारा मवेशी बाजार से बड़ी संख्या में मवेशियों का पिकअप वाहनों के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिकअप वाहन बाजार से मवेशी भरकर अन्य क्षेत्रों की ओर रवाना होते देखे गए हैं, लेकिन उनके दस्तावेजों और परिवहन की वैधता की जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

अमिता श्रीवास ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर जिले और प्रदेश का बढ़ाया मान

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

जिले की पर्वतारोही सुश्री अमिता श्रीवास ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह कर जिले एवं प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। एवरेस्ट अभियान से लौटने के पश्चात उन्होंने कलेक्टर जन्मेजय महोबे से सौजन्य भेंट की और अपने अभियान के अनुभव साझा किए। कलेक्टर ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अमिता श्रीवास को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता जिले सहित पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि अमिता ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, साहस और लगन के बल पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर प्रदेश की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

चरखापारा में हर घर नल योजना बनी शोपीस, वर्षों बाद भी नहीं मिला पानी, ग्रामीणों में आक्रोश

धर्मजयगढ़/मूक पत्रिका

धर्मजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत चरखापारा में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना वर्षों पहले शुरू की गई थी। गांव में पाइपलाइन और नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं, लेकिन आज तक योजना से एक बूंद पानी भी ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार की गई व्यवस्था केवल दिखावा बनकर रह गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है गांव के लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में उन्हें पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई परिवार हैंडपंप और अन्य अस्थायी स्रोतों पर निर्भर हैं, जहां भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन आज तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब हर घर नल योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, तो चरखापारा के लोग आज भी पानी की समस्या से क्यों जूझ रहे हैं। योजना अधूरी छोड़ने और संचालन शुरू नहीं होने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द योजना चालू कर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

पंचायतों में रोजगार दिवस के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं से किया गया जागरूक

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, रोजगार सृजन तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को गति देने के उद्देश्य से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सोमवार को रोजगार दिवस एवं प्रधानमंत्री आवास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनरेगा एवं आवास योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी प्रदान की गई तथा अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक पहल की जा रही है। रोजगार दिवस के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार मांग पंजीयन, श्रमिक जागरूकता, परिसंपत्ति निर्माण, जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यों तथा आगामी वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। ग्रामीण श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रावधानों, रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया, मजदूरी भुगतान व्यवस्था एवं उपलब्ध कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मोर गांव-मोर पानी अभियान के तहत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन संरचनाओं के निर्माण के बारे में विस्तार से बताया गया। वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए तालाब गहरीकरण, आजीविका डबरी निर्माण, जल संचयन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। आगामी पौधरोपण अभियान की सफलता के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन, गड्ढा खुदाई, पौधों की उपलब्धता एवं संरक्षण संबंधी तैयारियों से भी अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए हितग्राहियों को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को जल एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। साथ ही विकसित भारत-जी-रामजी अभियान की प्रमुख विशेषताओं एवं उद्देश्यों की जानकारी भी दी गई। मनरेगा योजना की जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से भी ग्रामीणों तक पहुंचाई गई। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों, मनरेगा हितग्राहियों, अधिकारियों-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की।

गांव में चल रहा था जुआ फड़, पुलिस रेड में 14 जुआरी पकड़ाए, लाखों की नगदी व मोटरसाइकिल जब्त

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

जिले में जुआ और सट्टे पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में इसी कड़ी में शिवरीनारायण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सिंघुल-भदराखार में चल रहे जुआ फड़ पर ताबड़तोड़ रेड मारकर 14 जुआड़ियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दिनांक 07 जून 2026 की देर शाम मिली सूचना के आधार पर शिवरीनारायण पुलिस ने घेराबंदी कर जुआ फड़ पर छापा मारा। पुलिस को देखते ही जुआड़ी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन टीम की मुस्तैदी से सभी को मौके पर ही दबोच लिया गया। पुलिस ने जुआड़ियों के कब्जे से कुल 1 लाख 03 हजार 800 रुपये नगद, दो मोटरसाइकिल (स्प्लेंडर पल्स ष्टत्र22ङ्ग7021 एवं स्क्क 125), 52 पत्ती ताश की गड्डी, प्लास्टिक बोरी और फट्टी जब्त की है। जब्त मोटरसाइकिलों की अनुमानित कीमत करीब 80 हजार रुपये बताई गई है। सभी 14 आरोपियों के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में दो अलग-अलग अपराध दर्ज कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत विधिवत कार्रवाई की गई। बाद में आरोपियों को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी के.पी. सिंह, प्रधान उप निरीक्षक रितेश परमार, प्रधान आरक्षक छगन साहू, आरक्षक पतिराम यादव, टुकेश्वर डडसेना, कुलदीप खुंटे, बलराम यादव, राजेश कौशिक सहित शिवरीनारायण पुलिस स्टाफकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सुशासन तिहार में प्राप्त जन शिकायतों एवं आवेदनों का करें समयबद्ध निराकरण

आगामी खरीफसीजन की तैयारियों की समीक्षा, किसानों को नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की परेशानी – कलेक्टर

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने आगामी खरीफ सीजन, मानसून पूर्व तैयारियों, वृक्षारोपण अभियान, पूरक परीक्षा, शाला प्रवेश उत्सव, पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश वितरण की तैयारियो, स्वच्छता एवं जल संरक्षण कार्यों तथा सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने आगामी खरीफ फसल सीजन के दृष्टिगत कृषि विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद, बीज एवं सिंचाई से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। किसानों को खाद, बीज एवं सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने जिले में उर्वरकों एवं बीजों के भंडारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए क्षमता के विरुद्ध उपलब्ध स्टॉक एवं भंडारण व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर ने किसानों को नैनो यूरिया एवं अन्य उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग के प्रति जागरूक करने तथा इसके लाभों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगामी मानसून में जिले में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों, शासकीय कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक परिसरों में अधिक से अधिक पौधरोपण की तैयारी सुनिश्चित करने कहा। कलेक्टर ने वन विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं रेशम विभाग को पौधों की उपलब्धता, रोपण स्थलों के चयन तथा संरक्षण की आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के साथ-साथ पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल की भी प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि लगाए गए पौधों का बेहतर जीवित प्रतिशत सुनिश्चित हो सके।

बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को आगामी पूरक परीक्षाओं के लिए छात्र-छात्राओं को कराई जा रही तैयारी की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र के लिए शाला प्रवेश उत्सव का प्रभावी आयोजन करने, विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकों एवं गणवेश का वितरण सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश उपलब्ध हो जाएं, जिससे अध्ययन कार्य प्रभावित न हो। कलेक्टर ने प्रत्येक जनपद पंचायत में कम से कम एक ग्राम पंचायत को चयन कर प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अन्य ग्राम पंचायत को प्लास्टिक मुक्त के रूप में विकसित करने कहा। इसके लिए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा फिकल स्लज प्रबंधन के प्रभावी संचालन करने कहा। उन्होंने जल संरक्षण एवं जल संचय से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्षा जल के अधिकतम संग्रहण एवं संरक्षण के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता एवं जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को जनभागीदारी के साथ अभियान के रूप में संचालित किया जाए, ताकि स्थायी एवं प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सकें तथा जिले में जल संसाधनों का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ उन्होंने अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत लाल झंडा लगाकर कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में सुशासन तिहार के दौरान आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्राप्त सभी आवेदनों एवं जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण किया जाए। उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की अद्यतन जानकारी विभागीय वेबसाइट एवं जांजगीर-चांपा निर्माण पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यों की पारदर्शिता एवं सतत निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

संक्षिप्त समाचार

ईरागांव में धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर रोक, ग्रामसभा के निर्णय के बाद लगाया सूचना बोर्ड

मूक पत्रिका/भानुप्रतापपुर। क्षेत्र के ग्राम ईरागांव में धर्मांतरण गतिविधियों को लेकर एक सूचना बोर्ड लगाया गया है, जिसमें ईसाई धर्म प्रचारक पादरी एवं पास्टरों के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार यह निर्णय ग्रामसभा में चर्चा के बाद लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद कुछ लोगों के गांव की परंपराओं, पूजा-पद्धति, देवी-देवताओं एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से दूरी बनाने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी को देखते हुए ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर धर्मांतरण गतिविधियों के उद्देश्य से आने वाले पादरी-पास्टरों के गांव में प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में गांव में सूचना बोर्ड भी स्थापित किया गया है। बैठक में ग्राम पटेल प्रयाग सिंह कोरेटी, जिला पंचायत सदस्य देवेन्द्र टेकाम, भागवत कोरेटी, मयाराम आंचला, पुखराज आंचला, गैंद सिंह हिडको, ज्वाला प्रसाद जैन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

निवेशकों के लिए सलाहः पक्का रिटर्न देने का वादा करने वाले अनधिकृत लोगों से सावधान रहें

भिलाई - भिलाई और आस-पास के इलाकों के निवासियों और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया और लोकल न्यूज प्लेटफॉर्म पर चल रही खबरों को देखते हुए सावधानी बरतें। इन खबरों में तोमन साहू नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है, जो खुद को गलत तरीके से एंजल वन लिमिटेड से जुड़ा हुआ बताता है और कंपनी के नाम पर लोगों से पैसे मांगता है, जिसमें पक्का रिटर्न देने का वादा आदि भी करता है।

एंजल वन लिमिटेड यह साफ करना चाहती है कि कंपनी ने जनवरी 2024 में तोमन साहू के साथ अपना संबंध खत्म कर दिया था, जो पहले एक ऑथराइज्ड पर्सन (एआई-अधिकृत व्यक्ति) था। संबंध खत्म होने के बावजूद, वह खुद को गलत तरीके से एंजल वन लिमिटेड से जुड़ा हुआ बताता रहा।

आम लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की जानकारी की पुष्टि कर लें जो किसी वित्तीय संस्थान का प्रतिनिधि होने का दावा करता है। इसके लिए वे एंजल वन की वेबसाइट पर मौजूद ऑथराइज्ड पर्सन वेरिफिकेशन सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर तब जब वे किसी पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हों।

एंजल वन एक पब्लिकली लिस्टेड वित्तीय सेवा कंपनी है जो एक रेगुलेटेड ढांचे के तहत काम करती है। कंपनी अनधिकृत व्यक्तियों के जरिए निवेश नहीं मांगती है और न ही पर्सनल अकाउंट के जरिए क्लाइंट का पैसा लेती है। जो निवेशक निवेश या ट्रेड करना चाहते हैं, उन्हें केवल एंजल वन के आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या कंपनी के अन्य वेरिफाइड याति सत्यापित चैनलों के जरिए ही ऐसा करना चाहिए।

एंजल वन अपने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अपने नाम के गलत इस्तेमाल या अनधिकृत प्रतिनिधित्व के मामलों में उचित कार्रवाई करती है। कंपनी निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने और केवल वेरिफाइड और अधिकृत चैनलों के जरिए निवेश को बढ़ावा देने का काम भी करती रहती है।

अगर किसी व्यक्ति ने गारंटीड रिटर्न के भरोसे किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के पास सीधे पैसे जमा किए हैं, तो उन्हें मदद के लिए संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए।

वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए निवेशकों की जागरूकता और सावधानी सबसे मजबूत उपाय हैं। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें और अनौपचारिक आश्वासनों, सोशल मीडिया दावों या बहुत ज्यादा या गारंटीड रिटर्न के वादों पर भरोसा करने से बचें।

डिप्टी सीएम एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव और मेयर संजय पांडेय में गजब की आत्मीयता

ये ट्यूनिंग बताती है कि आएंगे जगदलपुर के और अच्छे दिन

जगदलपुर को मिलेगा विकास का नया आयाम- पवन कुमार नाग

मूक पत्रिका/जगदलपुर। नगर में दो दिनों के भीतर नगरीय प्रशासन मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव और जगदलपुर के महापौर संजय पांडेय के बीच जो ट्यूनिंग और आत्मीयता देखने को मिली है, वह इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जगदलपुर के और अच्छे दिन आने वाले है तथा नगर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

दरअसल उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जो नगरीय प्रशासन विभाग के भी मंत्री हैं, वे पिछले दो दिनों से जगदलपुर में हैं।वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी यहां मौजूद हैं। इन दोनों वरिष्ठ मंत्रियों ने नगर में चल रहे जनहित के विकासमूलक निर्माण कार्यों का जायजा लिया। श्री साव और श्री कश्यप ने महापौर संजय पांडेय द्वारा कराए जा रहे कार्यों और उनकी लगनशीलता को जमकर सराहा भी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यपआज रविवार को महापौर संजय पांडे के निवास पर पहुंचे। यहां पांडेय परिवार ने उनका आत्मीय स्वागत किया। नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव और महापौर संजय पांडेय के बीच लगातार दो दिन से अच्छी ट्यूनिंग और बड़ी आत्मीयता देखने को मिली।

राजनीति में आत्मीय संबंधों का बड़ा महत्व होता है महापौर के निवास अरुण साव का जाना इस बात का सूचक है कि महापौर संजय पांडेय जिस प्रकार शहर के विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं, उससे उप मुख्यमंत्री अरुण साव पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। संजय पांडेय को मोरल सपोर्ट देते हुए उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने जगदलपुर को विभाग की ओर से पर्याप्त मदद करने का भरोसा दिलाया है। अब यह तय माना जा रहा है कि जगदलपुर अब महानगरों की तरह सुविधा संपन्न बनेगा, शहर के और अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसमें मंत्री श्री साव का बहुत ज्यादा सहयोग रहेगा। जिस प्रकार से राजनीतिक तालमेल है उससे लगता है कि अब शहर के विकास हेतु कई योजनाएं शुरू होंगी। जगदलपुर के विकास के लिए महापौर संजय पांडेय को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव का हमेशा भरपूर सहयोग मिलता आया है।

खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने किया तहसील कार्यालय का घेराव

घेराव में शामिल हुए पूर्व विधायक चंदन कश्यप = किसान हित में भानपुरी तहसीलदार को ज्ञापन

मूक पत्रिका/जगदलपुर। इन दिनों प्रदेश सहित बस्तर जिले की भानपुरी तहसील के किसान खाद बीज कि कमी से जूझ रहें हैं। खाद की इस समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।

किसानों को संबोधित करते हुए नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, शासन प्रशासन मौन हैं। शासन प्रशासन द्वारा किसानों को उपज को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से खाद आपूर्ति रोकी जा रही है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष धनुर्जय नेताम ने कहा कि फसल बुआई के समय से लेकर अब तक किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। खाद की कमी का भरपूर फायदा बिचौलिए उठा रहें हैं। निजी खाद बीज विक्रेता कई गुना अधिक दामों मे रासायनिक उर्वरक खाद बेच रहे हैं। मजबूर किसान फसल के नुकसान को देख अधिक दामों पर भी खाद खरीदने को मजबूर हैं। किसानों की समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। सुध लेने वाला कोई नहीं है, विभाग मौन है कहीं न कहीं शासन प्रशासन द्वारा किसानों की उपज को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से खाद की आपूर्ति को रोका जा रहा है। पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान हमने किसानों के हित का ध्यान रखकर कार्य किया था, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा था और किसानों की आय में इजाफा हो रहा था। आज किसान भाजपा की सरकार में स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहें हैं। कांग्रेस पार्टी आज भी किसानों के साथ खड़ी है।

सोमवार को एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर तहसील कार्यालय करंदोला भानपुरी पहुंच कर ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण कराया गया। ज्ञापन में तत्काल पर्याप्त खाद की आपूर्ति करने की मांग करते हुए चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों मे खाद के मामले में यही स्थिति रही तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ उग्र आंदोलन करेगी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष धनुर्जय नेताम, ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष निलय कश्यप, वरिष्ठ कांग्रेसी श्याम दीवान, श्यामसुंदर पांडे, लखेश्वर कश्यप आदिवासी ब्लॉक अध्यक्ष बबलू बघेल, श्यामकुमारी ध्रुव, महेंद्र पाढ़ी, अनिल बघेल, पुनऊ कश्यप, दया बघेल, जेटू कोर्राम, कृष्णा कश्यप, जीवन सेठिया, सोनसिंग कश्यप, मोसू बघेल, मंगल सेठिया, फागू बघेल सहित बड़ी संख्या में किसान, मंडल, सेक्टर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सदस्य व मंडल प्रभारी, युवक कांग्रेस एवं सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।

प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर वन मंत्री केदार कश्यप ने किया पद्मश्री हेमचंद मांझी और साहित्यकार शिव कुमार पांडेय का सम्मान

विकास, विश्वास और जनकल्याण की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने विशेष जनसंपर्क अभियान जारी

मूक पत्रिका/जगदलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, विकास, विश्वास और जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश के वनमंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर पहुंचकर पद्मश्री सम्मान से अलंकृत प्रसिद्ध वैद्यराज हेमचंद मांझी तथा क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार शिव कुमार पाण्डेय से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मंत्री केदार कश्यप ने दोनों प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया तथा समाज, संस्कृति, साहित्य और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में उनके योगदान की सराहना की।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और देश आत्मनिर्भरता तथा समावेशी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रेरणास्रोत व्यक्तित्वों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है तथा उनके अनुभव और मार्गदर्शन से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जगदलपुर जिला सहकारी बैंक उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा तथा नारायणपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के बैठक में गुंजा मोर संग चलव रे गीत, मस्तुरिया को किया याद

मूक पत्रिका/साजाः- छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना साजा एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी साजा की संयुक्त बैठक रविवार को साजा रेस्ट हाऊस में उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। बैठक का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी की आरती एवं वंदना के साथ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सेनानियों एवं कार्यकर्ताओं ने जनकवि लक्ष्मण मस्तुरिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके अमर गीतों मोर संग चलव रे एवं मैं बंदत हंव दिन-रात वो मोर धरती मैया का सामूहिक गायन किया।

बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना साजा के खड़ अध्यक्ष श्रवण कुमार साहू के नेतृत्व में किया गया। बैठक में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, शहर अध्यक्ष बेमेतरा फौजी सूर्या सिंह चौहान, खड़ अध्यक्ष सुनील वर्मा, उपाध्यक्ष कमलेश साहू, युवा अध्यक्ष राज साहू, खड़ महामंत्री जितेन्द्र राजपूत, सेनानी कुश साहू, लीलाराम साहू, वीरसिंह साहू सहित सैकड़ों सेनानियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

बैठक में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी भाषा एवं छत्तीसगढ़िया समाज के स्वाभिमान, अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वक्ताओं ने वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ी अस्मिता की रक्षा तथा जनहित के मुद्दों पर संगठित होकर कार्य करने का संकल्प लिया। उपस्थित सेनानियों ने समाज सेवा, जनजागरण एवं छत्तीसगढ़ महतारी के मान-सम्मान के लिए निरंतर संघर्षरत रहने का संकल्प दोहराया।

नये सेनानियों ने ग्रहण की सदस्यता- बैठक के दौरान संगठन विस्तार अभियान के तहत विवेक कुमार, बसंत कुमार, त्रिलोक चंद, संजय निर्मलकर एवं तुषार वर्मा सहित अनेक युवाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। संगठन पदाधिकारियों ने नवसदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ के हितों के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

बैठक का समापन छत्तीसगढ़ महतारी के जयघोष एवं संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने के संकल्प के साथ हुआ।

झपटमारी के दो और फरार आरोपी रायपुर से गिरफ्तार, लूटा गया मशरूका बरामद

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर/ कांकेरः- उत्तर बस्तर कांकेर क्षेत्र में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्गुकोन्दल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विगत दिनों भानुप्रतापपुर-दुर्गुकोन्दल मुख्य मार्ग पर एक महिला से हुई झपटमारी की वारदात में शामिल दो शातिर फरार आरोपियों को पुलिस ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर राजधानी रायपुर से धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से प्रार्थिया से लूटा गया माला भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पुलिस की इस त्वरित और सटीक कार्रवाई से क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप का माहौल है। घटना के संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार, बीती 3 जून 2026 को ग्राम घोटिया निवासी प्रार्थिया कुमारीबाई पति त्रिभुवन लाल साहू अपने खेत विक्रमगंज से काम खत्म कर वापस अपने घर लौट रही थीं।

इसी दौरान भानुप्रतापपुर-दुर्गुकोन्दल मुख्य मार्ग पर विक्रमगंज के समीप एक सफेद रंग की कार आकर रुकी, जिसमें तीन युवक और एक युवती सवार थे। कार से उतरे एक अज्ञात युवक ने बातचीत करने के बहाने प्रार्थिया के गले में पहनी हुई माला को सोने की माला समझकर झपट लिया और अपने अन्य साथियों के साथ कार में बैठकर मौके से फरार हो गया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना दुर्गुकोन्दल में अपराध क्रमांक 15/2026, धारा 304 एवं 112(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन यानी 4 जून 2026 को एक आरोपी आशीष भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि घटना के बाद से ही शेष आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक उत्तर बस्तर कांकेर निखिल राखेचा (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन में एक विशेष रणनीति तैयार की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर आकाश श्रीमाल एवं एसडीओपी भानुप्रतापपुर शेर बहादुर सिंह ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में फरार आरोपियों की पतासाजी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने आधुनिक साइबर सेल की मदद और तकनीकी साक्ष्यों को खंगालते हुए आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की। इसके बाद पुलिस टीम ने राजधानी रायपुर में दबिश देकर फरार आरोपी सूर्यकांत गुप्ता उर्फ सूर्या (21 वर्ष), निवासी रावणभाठा रायपुर (थाना खमतराई) और माही उर्फ मनीषा बंजारे (23 वर्ष), निवासी मोवा रायपुर (थाना पंडरी) को सफलतापूर्वक हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा की गई कड़ी पूछताछ में दोनों ही आरोपियों ने दुर्गुकोन्दल क्षेत्र में घटित इस झपटमारी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रार्थिया से छीना गया माला भी बरामद कर लिया है। इस पूरी अंधे कत्ल और झपटमारी की गुत्थी को सुलझाने तथा आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में दुर्गुकोन्दल पुलिस और साइबर सेल की टीम का सराहनीय योगदान रहा। इस पूरी कार्रवाई में मुख्य रूप से निरीक्षक प्रहलाद यादव, सहायक उपनिरीक्षक महावीर प्रसाद मिश्रा, वीरेंद्र बुंदेला, प्रधान आरक्षक गजेंद्र गेंडेरे, आरक्षक अवधराम नाग, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक यशवंत श्याम, प्रधान आरक्षक सचिन सोरी, आरक्षक प्रणय यादव, जितेंद्र नैग, भूपेश नेताम और हेमेश्वर मण्डवी की विशेष और सक्रिय भूमिका रही। पुलिस प्रशासन की इस मुस्तैदी की स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने खुलकर सराहना की है।

किसानों को समय पर मिले खाद-बीज और ऋण, किसी को न हो परेशानी : कलेक्टर

खरीफसीजन की तैयारियों की समीक्षा, अमानक खाद बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

मूक पत्रिका/ बीजापुर/आशीष पदमवार। खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले किसानों को खाद, बीज और कृषि ऋण समय पर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को जिला कार्यालय में आयोजित कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक में कलेक्टर विश्वदीप ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खाद-बीज वितरण में किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी समितियों में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करते हुए जरूरतमंद किसानों तक समय पर सामग्री और ऋण पहुंचाया जाए।

बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026 के लिए खाद-बीज भंडारण, धान बीज वितरण और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले की सहकारी समितियों में वर्तमान में 6329 क्विंटल धान बीज, 1962 मीट्रिक टन यूरिया, 500 मीट्रिक टन डीएपी, 49 मीट्रिक टन एनपीके और 46 मीट्रिक टन पोटाश उपलब्ध है।

कलेक्टर ने सभी शाखा प्रबंधकों और समिति प्रबंधकों को निर्देश दिए कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से नगद ऋण एवं खाद-बीज के लिए ऋण वितरण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भी अपने-अपने क्षेत्रों में खाद-बीज भंडारण और ऋण वितरण की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। वहीं कृषि विभाग को अमानक खाद के वितरण पर सख्त निगरानी रखने तथा शासन के निर्देशों के विपरीत उर्वरक विक्रय करने वाले लाइसेंसधारी विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

कलेक्टर ने जिला विपणन अधिकारी को निर्देशित किया कि समितियों द्वारा उपार्जित धान का शत-प्रतिशत उठाव एक सप्ताह के भीतर कराया जाए। साथ ही धान उठाव पूरा होने के बाद लेखा मिलान की प्रक्रिया भी तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर भूपेंद्र अग्रवाल, सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक, सहकारी समितियों के प्रबंधक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सहायक संचालक कृषि, जिला विपणन अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना से बदली जिंदगी, छबील कुमार वर्मा का पक्के मकान का सपना हुआ साकार

मूक पत्रिका/बेमेतरा,8जून 2026 शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से ग्राम खेड़ा के निवासी श्री छबील कुमार वर्मा का वर्षों पुराना पक्के मकान का सपना आज साकार हो गया है।

श्री छबील कुमार वर्मा पहले अपने परिवार के साथ कच्चे और जर्जर मकान में निवास करते थे। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था तथा गर्मी और सर्दी के मौसम में परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सीमित आय के कारण स्वयं का पक्का मकान बनाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था।

इसी दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत उनका चयन हुआ। योजना के तहत प्राप्त वित्तीय सहायता से उन्होंने अपना सुंदर एवं सुरक्षित पक्का मकान तैयार कराया। आज उनका परिवार नए घर में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहा है। श्री वर्मा बताते हैं कि पक्का मकान बनने से उनके परिवार को सुरक्षा और सुविधा दोनों मिली हैं। अब बरसात के मौसम की चिंता नहीं रहती तथा बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध हुआ है। नए घर ने उनके परिवार में आत्मविश्वास और खुशहाली का संचार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना ने न केवल उन्हें पक्का घर दिया है, बल्कि सम्मान और सुरक्षित भविष्य का भरोसा भी प्रदान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आज हजारों ग्रामीण परिवारों के जीवन में बदलाव ला रही है और ÷हर परिवार का सपना, पक्का घर अपना÷ के संकल्प को साकार कर रही है। श्री छबील कुमार वर्मा की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि शासन की योजनाएं सही हितग्राहियों तक पहुंचकर उनके जीवन में खुशियों की नई रोशनी ला सकती हैं।

प्रतिभाओं के सम्मान से गौरवान्वित हुआ चौहान समाज, शिक्षा व करियर मार्गदर्शन का मिला अमूल्य संदेश

बरमकेला :- अघरिया भवन बरमकेला में चौहान समाज ब्लॉक द्वारा प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह एवं करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरायपाली विधायक चातुरी नंद एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व कलेक्टर कुमारलाल चौहान, डीएमसी नरेश चौहान, बरमकेला जनपद अध्यक्ष विद्या किशोर चौहान तथा ब्लॉक अध्यक्ष विषिकेशन चौहान की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का सफल मंच संचालन राजेंद्र चौहान एवं गोपाल बाघे ने किया।

इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान कर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक चातुरी नंद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में शिक्षा को और अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर लगभग 25 मेधावी विद्यार्थी 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने

हैं, जिनकी संख्या भविष्य में सैकड़ों तक पहुंचनी चाहिए।

उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा उन्हें आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किया। वहीं सारंगढ़ के डीएमसी नरेश चौहान ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया।

कार्यक्रम में 10वीं एवं 12वीं कक्षा में वाले विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में संकीर्तन नन्द,देवराज दीपक ,सुभाष चौहान, चमरा चौहान, कमल चौहान ने जोर लगाया

इस अवसर पर डॉ गोविंद चौहान, डॉ किशोर चौहान, पुनीत राम चौहान, विजय कांटे, गनेशी चौहान, उजागर नन्द,ओमप्रकाश चौहान,,सुदर्शन चौहान, केदार चौहान, मुक्तेश्वर चौहान,संजय चौहान, महगुलाल चौहान,ठाकुर राम चौहान, सुधीर चौहान, गोवर्धन चौहान,रामेश्वर चौहान, धनीराम चौहान, गजेंद्र चौहान, लक्ष्मण चौहान, गंगाराम चौहान, के अलावा सैकड़ो 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने समाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सरसीवा क्षेत्र में उर्वरक निरीक्षक ने किया खाद दुकानों की जांच

मूक पत्रिका/सारंगढ़-बिलाईगढ़, 8 जून 2026/कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश और आशुतोष श्रीवास्तव उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में जिले के किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद, बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने हेतु उर्वरक निरीक्षको के द्वारा नियमित औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते रविवार को उर्वरक निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता के द्वारा जिले के सरसीवा क्षेत्र के विक्रय केंद्रों मेसर्स महामाया ट्रेडर्स , मेसर्स ऋषि ट्रेडर्स , मेसर्स प्रकाश ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया। अनियमितता पाए जाने पर मेसर्स प्रकाश ट्रेडर्स पेंड्रावन को नोटिस जारी किया गया है। वहीं जिले में अब तक 57 निजी एवं सहकारी केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है।

कार्यवाही - अनियमितता पाए जाने पर 27 केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, 8 विक्रय केंद्रों का अनुज्ञप्ति निलम्बित किया गया है तथा एक प्रकरण कालाबाजारी का कलेक्टर कोर्ट के अधीन है। जिले में निरंतर निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। किसी भी प्रकार कि अनियमितता पाए जाने पर एफ्सीओ कानून 1985 के तहत कार्यवाही किया जाएगा।

खाद भंडारण एवं वितरण- वर्तमान में खरीफ की तैयारी जोरो पर है जिले में रासायनिक खाद 16805.360 मैट्रिक टन एवं बीज 15801 क्विंटल उपलब्ध है किसानों के मांग अनुरूप पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया गया है। जिले में कुल 25390 मैट्रिक टन रासायनिक खाद भंडारण उपरांत 8554 मैट्रिक टन वितरण किया गया है तथा 5053 क्विंटल बीज वितरण किया गया है। जिले में यूरिया सहकारी क्षेत्र में अब तक 12295 मैट्रिक टन , डीएपी 1608 मैट्रिक टन , एनपीके 1489 मैट्रिक टन, एमओपी 996 मैट्रिक टन तथा 1266 मैट्रिक टन खाद उपलब्ध कराया गया है जो कि खरीफ वर्ष 2025 मे वितरण किये गये खाद का 66त्न प्रतिशत है।

अफवाह से दूर रहने अपील- जिला प्रशासन कृषको के हित में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और सुगम वितरण के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों से अपील है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकतानुसार उर्वरक प्राप्ति हेतु विक्रय केंद्रों से संपर्क करें।

स्कूल शिक्षा विभाग के पेंशन, सर्विस बुक, अवकाश स्वीकृत जैसे कार्यों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं : कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू

कलेक्टर ने कहा, पढ़ाते समय कोई भी शिक्षक कक्षा में मोबाईल का उपयोग नहीं करेंगे

कलेक्टर ने की स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा

मूक पत्रिका/सारंगढ़-बिलाईगढ़, 8 जून 2026/कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी, सभी प्राचार्यो की उपस्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग का समीक्षा किया। उन्होंने मध्यान्ह भोजन में दाल भात सब्जी आदि को स्वादिष्ट, सफाई और सुरक्षा के साथ बनाने के निर्देश देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल प्रारम्भ के पूर्व मरम्मत, पोताई, आदि कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। मरम्मत योग्य शौचालय को सरपंच या सीईओ पंचायत के माध्यम से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि, जिले में कोई भी स्कूल शौचालय विहीन नहीं होना चाहिए। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने बैठक में सभी प्राचार्यो को कहा कि विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी दसवीं बारहवीं बोर्ड में अच्छा परिणाम के लिए सभी आगे भी अच्छा मेहनत करें। उन्होंने अनुशासन का पालन को जोर देते हुए कहा कि, पढ़ाते समय कोई भी शिक्षक कक्षा में मोबाईल का उपयोग नहीं करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि, पेंशन, सर्विस बुक अपडेट करने, अवकाश स्वीकृत, ईकेवायसी, जैसे विभागीय कार्यो में किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की गतिविधि किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने 10 से कम बच्चों वाले स्कूलों के गांव में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा और पालक से बच्चों को सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजने के कारण की जानकारी लेकर मांग, शिकायत आदि का निराकरण करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने गणवेश वितरण करने , स्कूलों में निरंतर खेल गतिविधि करने , जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कैंसरमुक्त करने के लिए पालकों के सहमति पर बालिकाओं को एचपी वैक्सीन देने के निर्देश दिए।

कलेक्टर का सख्त संदेश, पीएम आवास और शौचालय निर्माण की गुणवत्ता में कमी या रिश्वत की मांग पर होगी कार्यवाही

कलेक्टर ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा

मूक पत्रिका/ सारंगढ़ बिलाईगढ़ 8 जून 2026/कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का समीक्षा किया गया। कलेक्टर ने पीएम आवास ग्रामीण के प्रारम्भ हुए कार्यो को बरसात के पहले तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। वहीं विवादित प्रकरण में पटवारी और राजस्व अधिकारी के माध्यम से विवाद का निराकरण करने के निर्देश दिए। पीएम आवास और शौचालय निर्माण की गुणवत्ता में कमी, पंचायत अधिकारी, रोजगार सहायक या अन्य के द्वारा पीएम आवास स्वीकृत, राशि जारी करने जैसे कार्यो के लिए रिश्वत की मांग करने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की चेतावनी दी। वहीं मनरेगा के कार्यो से लोगों को रोजगार ज्यादा मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं और बिहान आदि में बैंक द्वारा लोन स्वीकृति को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन, उद्यानिकी विभाग और मनरेगा से पेड़ पौधों से विहीन पठार जैसे विरान क्षेत्र में सीड बॉल से पौधरोपण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले की महिलाओं को महिला किसान सशक्तिकरण योजना से मुर्गी, बकरी पालन, सब्जी उत्पादन, आर्गेनिक खेती आदि से लाभ देकर उन्हें उन्नति दिलाने के निर्देश दिए।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कलेक्टर ने जिले में शौचालय, सामूहिक शौचालय का निर्माण को स्कूल, कॉलेज परिसर जैसे उचित स्थान पर करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रो से निकले वाले मलीय कीचड़ का प्रबंधन के लिए जिले में फिक्कल स्लक मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की गई है, जिसमें डी स्लज वाहन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो से न्यूनतम दर पर सेप्टीक टैंक खाली कराने का कार्य किया जाता है।

इस अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत बर्मन, जूली तिर्की, सीईओ जनपद पंचायत राधेश्याम नायक, प्रतीक प्रधान, अजय पटेल, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एसडीओ और इंजीनियर, मनरेगा और बिहान के प्रभारी, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन निमिष कुमार आदि उपस्थित थे।

सारंगढ़ बस स्टैंड में पानी और प्रसाधन को लेकर यात्री परेशान...जिला प्रशासन से तत्काल व्यवस्था की मांग

मूक पत्रिका/सारंगढ़: जिले के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, बस स्टैंडों और सरकारी कार्यालयों में प्रसाधन (शौचालय) और पेयजल की खराब व्यवस्था को लेकर आम नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई स्थानों पर शौचालय गंदगी से भरे हुए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है और नियमित सफाई के अभाव में उनका उपयोग करना मुश्किल हो गया है। तो वहीं कहीं पर पानी के लिए तो व्यवस्था की गई है लेकिन पानी की ही उपलब्धता नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वच्छता को लेकर लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है।

नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी सार्वजनिक प्रसाधनों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, पानी एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा इसपर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पूरे सारंगढ़ क्षेत्र की नल जल व्यवस्था की हालत बहुत

खराब..जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी पानी की व्यवस्था को ठीक से उपलब्ध नहीं करा पा रही है प्रशासन!! आखिर क्या है कारण?

सारंगढ़ के तमाम क्षेत्रों और चौक चौराहों पर अगर नज़र दौड़ाया जाए तो पीने के पानी के लिए आमजनता को काफ़ी किल्लतों और समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जिनमें से एक प्रमुख है सारंगढ़ बस स्टैंड।

बता दें कि सारंगढ़ बस स्टैंड में आवागमन के लिए आम पब्लिक बस सर्विस का उपयोग करते हैं, जिनमें महिला और पुरुष से लेकर बच्चेबुढ़े भी होते हैं। बस स्टैंड में पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से आमजनता अथवा यात्रियों को पीने का पानी दुकान पर से खरीदकर पीना पड़ता है या फिर स्वरोजगार करने

वाले ठेलों से जाकर पानी लेना पड़ता है।

बता दें कि सारंगढ़ बस स्टैंड में महीने बीत गए किंतु आम जनजीवन को पानी की समस्याओं से प्रभावित होना पड़ रहा है।

यहां पर पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए वाटर डिस्पेंसर लगाया गया है किंतु जब उसमें पानी की व्यवस्था ही नहीं है तो कितना भी पैसा खर्च कर ले प्रशासन, अपनी लचर व्यवस्था को लेकर अपनी छवि भी नहीं बना पा रही है। जिला प्रशासन द्वारा तमाम विभागीय क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को लेकर काफी सवाल उठते रहते हैं किंतु आम जनजीवन को जीवन दायिनी जल ही नहीं मिल पा रहा है तो अन्य व्यवस्था को लेकर क्या ही बात करें।

सारंगढ़ में यात्रियों को पानी को लेकर होती है काफी दिक्कतें!!

यात्रियों को गर्मियों में पानी नहीं मिलने से वे बताते हैं कि पीने के पानी को उन्हें पैसे खर्च करके खरीदना पड़ता है तब जाकर उन्हें पीने के लिए यहां पर पानी उपलब्ध हो पाता है। और उन्हें पानी के साथ साथ स्वच्छ प्रसाधन की व्यवस्था भी नहीं मिल पाती।

जिला प्रशासन आमजनता के लिए व्यवस्थाओं को लेकर में गम्भीर नज़र नहीं आती तथा अपनी खराब व्यवस्थाओ को लेकर अपनी जवाबदारी नहीं दिखाती है। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बस स्टैंड पर स्वच्छ पेयजल की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, खराब पड़े नलों और टंकियों की तत्काल मरम्मत कराई जाए तथा यात्रियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

यात्रियों का कहना है कि बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थान पर पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन इस समस्या का शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएगा।

नहीं थम रहा टिमरलगा में उमेश पटेल का अवैध खनन, खनिज विभाग के मिलीभगत फल फूल रहा अवैध खनन

एक अवैध खदान में दस दस पोकलेन, उमेश पटेल का राज, प्रति दिन लाखों के राजस्व को हानि

सारंगढ़/मूक पत्रिका

सारंगढ़ जिले के टिमरलगा क्षेत्र में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। वही बात की जाए उमेश पटेल की तो कानून नियमों से बढ़ कर इनका सारंगढ़ के अधिकारीओ में दबदबा चलता है।दिन तो दिन रात में भी खुले आम बेधड़क से खनन किया जा रहा, जहां प्रशासनिक कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, वहीं उमेश रात दिन बड़े बड़े मशीनों से चूना पत्थर को लादकर निकलते देखा जा रहा । स्थानीय लोगों का कहना है कि खनिज विभाग नाम मात्र का रह गया है और उमेश करता है खुले आम बेधड़क अवैध खनन।

टिमरलगा के आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई साल से इस इलाके में गौण खनिज का अवैध उत्खन लगातार बढ़ा जा रहा है। किसी दिन में अगर राजस्व टीम कार्रवाई के लिए रवाना होता है, तो कुछ विभागीय दलाल खनिज माफ़ियाओं को गुप्त सूचना दे देते हैं फिर क्या खदान से हाईवा पोकलेन मशीनों को तत्काल खदान से बाहर किया जाता है। खदान को खाली देख कर अपना नाटकीय प्रदर्शन कर के वापस चले जाते हैं। या यू कहे कि यह सारा खेल केवल और केवल प्रशासन के मिलीभगत का खेल है और कभी कभी शासकीय कागज को कुछ कार्रवाई दिखा कर अपना नाटकीय कार्रवाई को अपना कड़ी कार्रवाई बताते हैं। इनकी खनिज माफ़ियाओं से संपर्क में रहना मतलब राजस्व की कितनी बड़ी हानि है। जरा सोचिए शासकीय अधिकारी हो कर भी और शासन से वेतन भोगी हो रहा प्रशासन के निर्धारित नियमों का खुला उल्लंघ कर के अपने पद का भी गलत उपयोग कर रहे हैं।

राजस्व रिकॉर्ड 1ह्य जमीनी हकीकत- सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जिले में गौण खनिज के लिए तय रॉयल्टी और परमिट के नियम हैं। वैध खदानों से ही खनिज निकालने की इजाजत है। लेकिन जमीनी स्तर पर टिमरलगा, आसपास दर्जनों जगहों पर बिना अनुमति के पत्थर निकाले जा रहे हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अवैध खन से सरकारी राजस्व को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं, नदी-नालों का रास्ता बदल रहा है।

कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं?- खनिज अधिनियम 1957 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत बिना अनुमति खन करना दंडनीय अपराध है।

इसमें 5 साल तक की सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान है। पकड़ी गई मशीनरी, वाहन भी राजसात किए जा सकते हैं। वही जिला प्रशासन सारंगढ़ इस क्षेत्र में टिमरलगा में स्थाई खनिज चेकपोस्ट बनाया जाए,अतिरिक्त बल दिया जाए ,वैध खदानों को बढ़ावा देकर अवैध खनन पर निर्भरता खत्म की जाए,अवैध खनन की सूचना देने वाले को इनाम की व्यवस्था हो। अवैध खनन का असर सिर्फ राजस्व पर नहीं पड़ रहा। ओवरलोड डंपरों से गांव की सड़कें टूट जा रही हैं। टिमरलगा जाने वाली मुख्य सड़क का भी हाल बेहाल हो गया है सड़कों पर गिट्टी डस्ट नेशनल हाईवे सड़क पर जम गया है,, धूल के कारण फसल भी प्रभावित हो रही है।

क्या कहते है सारंगढ़ खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा-इस संबंध में संपर्क किया गया मगर उन्हों ने कॉल नहीं उठाया।

कांकेर तहसीलदार के आदेश के बाद भी ज़मीन से नहीं हटा अवैध कब्ज़ा, पीड़ित ने पुलिस बल के साथ कब्ज़ा दिलाने की लगाई गुहार, जान से मारने की धमकी का आरोप

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर / :- कांकेर जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम मालगांव में एक ज़मीन विवाद को लेकर तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद भी कब्ज़ा न हटने का गंभीर मामला सामने आया है। प्रार्थी संदीप साहू ने तहसीलदार महोदय कांकेर के समक्ष एक नया आवेदन प्रस्तुत कर पुलिस बल की मौजूदगी में अपनी भूमि का मालिकाना हक (कब्ज़ा) वापस दिलाने की मांग की है।

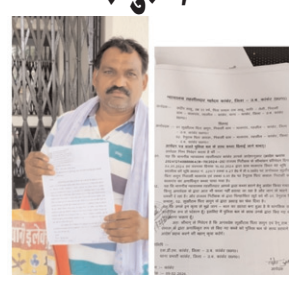

प्रार्थी का आरोप है कि न्यायालय द्वारा कब्ज़ा हटाने के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद अनावेदकों द्वारा न सिर्फ कब्ज़ा हटाने से इंकार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस मामले की प्रतिलिपि एसडीएम कांकेर और थाना प्रभारी कांकेर को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, आवेदक संदीप साहू (पिता समारू राम साहू, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम मालगांव) ने पूर्व में अपनी स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 229/7, कुल रकबा 0.27 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन किया था। माननीय तहसीलदार न्यायालय कांकेर के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा 4 जनवरी 2024 को किए गए सीमांकन और 16 फरवरी 2024 को तैयार किए गए पंचनामे में पाया गया था कि उक्त भूमि में से 0.08 हेक्टेयर पर गांव के ही सुखीराम (पिता सगुन) और 0.01 हेक्टेयर पर रैनूराम (पिता समारू) द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्ज़ा किया गया है।

इस सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय द्वारा पूर्व में ही अनावेदकों को कब्ज़ा हटाने हेतु आदेश जारी किया जा चुका था। प्रार्थी संदीप साहू ने अपने ताज़ा आवेदन में प्रशासन को अवगत कराया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अनावेदकों द्वारा आज दिनांक तक कब्ज़ा नहीं हटाया गया है। इसके विपरीत, राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के दौरान लगाए गए चिन्हांकित खूंटों को भी अनावेदक रैनूराम और सुखीराम द्वारा उखाड़कर फेंक दिया गया है। आवेदक का कहना है कि जब वे अपनी ज़मीन पर जाते हैं, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिससे उनके जान-माल को लगातार खतरा बना हुआ है।

इस पूरे घटनाक्रम के कारण प्रार्थी अत्यधिक मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं। प्रार्थी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए निवेदन किया है कि अनावेदकों द्वारा किए गए इस अवैध कब्ज़े को पुलिस बल की सहायता से हटवाया जाए ताकि उन्हें अपनी पैतृक भूमि का वास्तविक अधिकार मिल सके। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग और स्थानीय पुलिस इस संवेदनशील मामले पर क्या त्वरित कदम उठाती है।

रायगढ़ में कलाकारों का महाकुंभः छत्तीसगढ़ी-हिंदी फिल्म 'अभिशाप' के लिए लगे ऑडिशन, उमड़ी भारी भीड़

रायगढ़/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ी सिनेमा और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज रायगढ़ में एक बड़े स्तर के ऑडिशन का आयोजन किया गया। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में रात्रे फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली आगामी छत्तीसगढ़ी-हिंदी फिल्म 'ABHISHAP' (अभिशाप) के लिए ऑफलाइन ऑडिशन रखे गए, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही कलाकारों का तांता लगा रहा।

5 से 60 वर्ष के कलाकारों ने दिखाया दम-इस ऑडिशन की सबसे खास बात यह रही कि इसमें उम्र की कोई सीमा आड़े नहीं आई। फिल्म के मुख्य किरदारों (मेल एक्टर और फीमेल एक्ट्रेस) की तलाश के लिए 5 वर्ष के बच्चों से लेकर 60 वर्ष तक के बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। नए (फ्रेशर्स) और अनुभवी, दोनों ही तरह के कलाकारों ने कैमरे के सामने अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया।

?रायगढ़ की प्रतिभाओं को **मिलेगा बड़ा मंच-**फिल्म के डायरेक्टर और राइटर सूर्या रात्रे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही मंच की जरूरत है। फिल्म 'अभिशाप' के जरिए स्थानीय कलाकारों को अपनी कला को बड़े पर्दे पर दिखाने का एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर संतोष महंत और गुलशन दास महंत ने आयोजन की व्यवस्था और आए हुए कलाकारों के उत्साह की सराहना की। इस दौरान कास्टिंग टीम के सदस्य समरू सोनी, दुकालु खुट्टे और सोना चौहान भी मौजूद रहे, जिन्होंने बारीकी से कलाकारों की अभिनय क्षमता को परखा।

लोहरसिंह में 5 साल बाद भी अधूरी पड़ी पानी टंकी

नल जल योजना का उड़ रहा माखौल, गर्मी आते ही पानी की बढ़ रही किल्लत

रायगढ़/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत लोहरसिंह में विगत पांच साल पहले शुरू की गई पानी टंकी निर्माण योजना आज भी अधूरी पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी नल जल योजना के उद्देश्यों को बेअसर साबित कर रही है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है।

उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय से करीब 10 किमी दूर ग्राम पंचायत लोहरसिंह में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विगत पांच वर्ष पूर्व एक पानी टंकी के निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस योजना के तहत गांव के हर घर तक पाईप लाइन का विस्तार कर पानी पहुंचाना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और विभागीय उदासीनता के चलते अभी तक न तो पानी टंकी का निर्माण पूरा हो सका और न ही पूरी तरह से पाइन लाइन का विस्तार हो सका है। वहीं कुछ जगहों में पिछले साल पाइप लाईन का विस्तार हुआ भी था, लेकिन पानी टंकी अधूरी होने के कारण नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरे निर्माण के कारण हर साल गर्मी शुरू होते ही गांव में पानी समस्या बढ़ जाता है, वहीं इस बार तो अप्रैल माह में ही ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए पांच बोर में से तीन बोर पूरी तरह से सूख गए थे, जिससे दो बोर के सहारे ही पानी की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन इससे सभी घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में अब ग्रामीणों को प्रायवेट बोर पर निर्भर रहना पड़ रहा है, वहीं कई बार तो निजी बोर मालिक द्वारा यह भी बोल दिया जाता है कि बोर अपने लिए लगाए हैं, जिससे काफी दिक्कत होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि लोहरसिंह में पानी टंकी का अधूरा निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें पेयजल संकट से मुक्ति मिल सके।

तीन हजार लोग हो रहे प्रभावित- उल्लेखनीय है कि लोहरसिंह गांव में तीन हजार की जनसंख्या है, जो विगत दो माह से परेशान हो रहे हैं, साथ ही जब तक बरसात शुरू नहीं हो जाती तब तक यहां पानी की समस्या बनी रहती है। वहीं पिछले साल भी यही स्थिति उत्पन्न होने पर खेत के बोर से टैंकर से पानी पहुंचाया गया था, लेकिन इस साल पंचायत द्वारा दो-तीन बोर को सुधार कर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन घर-घर तक पानी अभी भी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में पंचायत के बोर से सिर्फपानी टंकी को भरा जा रहा है। जिससे ग्रामीणों को टंकी से पानी ढोकर नहाने व पीने के लिए उपयोग करना पड़ रहा है।

शिकायत का भी असर नहीं- स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यहां पानी टंकी का निर्माण कछुआ गति से चल रहा है। जिसको लेकर लगातार शिकायत भी की जाती रही है, लेकिन उसके बाद माहभर काम चलता है फिर एक साल के लिए बंद हो जाता है। यही कारण है कि पांच साल बाद भी टंकी तैयार नहीं हो पाया है। साथ ही संबंधित ठेकेदार को शिकायत करने पर उसके द्वारा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। वहीं गांव का सरपंच कामता गुप्ता ने बताया कि पानी टंकी निर्माण के लिए ठेकेदार को कई बार सूचना दी गई है और कलेक्टर को भी लिखित में दिया गया है। इसके बाद भी निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं हो रहा है। जिसका खामियाजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

योजना पर लग रहा बट्टा-ग्रामीणों की मानें तो एक तरफ शासन द्वारा नल-जल योजना को लेकर जोरों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, तो वहीं यह योजना अब सफेद हाथी साबित होने लगा है, क्योंकि लोहरसिंह में पानी की समस्या को देखते हुए विगत पांच साल पहले योजना के तहत पानी टंकी तैयार होना था, लेकिन इतने दिन बित जाने के बाद भी यह टंकी अधूरी पड़ी है। जिसे बनाने के लिए न तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा और न ही संबंधित ठेकेदार, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर मरीजों को फल एवं बिस्किट वितरित कर दी श्रद्धांजलि

बरमकेला/मूक पत्रिका

स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर शिव सेवा संकल्प संस्थान द्वारा बरमकेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों एवं जरूरतमंद लोगों के बीच फल एवं बिस्किट का वितरण कर स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के माध्यम से संस्था ने मानव सेवा और समाज कल्याण का संदेश देते हुए उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दो मिनट का मौन रखकर की गई। उपस्थित लोगों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में सदैव समाज सेवा, मानवीय मूल्यों और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके कार्य और विचार आज भी लोगों को समाजहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके पश्चात शिव सेवा संकल्प संस्थान के सदस्यों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना तथा उन्हें फल एवं बिस्किट वितरित किए। मरीजों एवं उनके परिजनों ने इस सेवा कार्य के लिए संस्थान के प्रति आभार व्यक्त किया। संस्थान के सदस्यों ने मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की सहायता और पीड़ित मानवता की सेवा ही किसी महान व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की स्मृति को जीवंत रखने का सबसे अच्छा माध्यम उसके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना और समाज के हित में कार्य करना है। स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह का जीवन सेवा, सहयोग और सामाजिक समरसता का प्रतीक था। उनके द्वारा स्थापित मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही यह सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश पटेल, शिव सेवा संकल्प संस्थान के सक्रिय सदस्य आशीष त्रिपाठी, शिवम सिंह (गोलू त्योंधरी) सहित संस्थान के अनेक सदस्य, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्मरण किया। उपस्थित जनों ने उनके द्वारा किए गए सामाजिक एवं जनकल्याणकारी कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन सेवा, समर्पण और मानवता की मिसाल था। सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने तथा समाज के जरूरतमंद वर्ग की सहायता के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प भी लिया।

पावर प्लांट के बाहर ठेका श्रमिकों का धरना : 200 से अधिक कर्मचारियों को हटाने का आरोप, छंटनी के विरोध में प्रदर्शन

सक्ती/मूक पत्रिका

जिले के डभरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट के सामने ठेका श्रमिक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। दरअसल हादसे में 25 श्रमिकों की मौत के बाद एनजीएसएल (ह्लस्रू) कंपनी के अधीन कार्यरत श्रमिकों को थोक में निकलने और रोजगार समाप्त किए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ।

200 से अधिक श्रमिकों को किया पृथक- श्रमिकों का कहना है कि, 14 अप्रैल 2026 को प्लांट में हुए भीषण बॉयलर हादसे के बाद से उत्पादन एवं रखरखाव संबंधी कार्य लगभग ठप पड़े हैं और इसके बाद बड़ी संख्या में ठेका कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के काम से अलग किया जा रहा है। धरना दे रहे श्रमिकों के अनुसार, एनजीएसएल कंपनी के माध्यम से प्लांट में करीब 400 ठेका कर्मचारी कार्यरत थे। हादसे के बाद 200 से अधिक श्रमिकों को मौखिक रूप से कार्य से पृथक कर दिया गया है।

मांगों को लेकर जमकर किया प्रदर्शन- कर्मचारियों का आरोप है कि, न तो उन्हें लिखित आदेश दिया गया और न ही वैकल्पिक रोजगार की कोई व्यवस्था की गई। इससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। करीब 70 श्रमिकों ने गेट नंबर-1 के सामने एकत्र होकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने कहा कि, जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

ये हैं प्रमुख मांगे-प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में प्रभावित सभी श्रमिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराना अथवा नई एजेंसी में समायोजित करना, मई और जून माह का वेतन भुगतान, अतिरिक्त तीन माह का मुआवजा, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं एनओसी जारी करना तथा पीएफ, ईएसआईसी और बोनस सहित अन्य लंबित देयों का भुगतान शामिल है।

क्षेत्र में चर्चा का विषय बना यह आंदोलन- गौरतलब है कि, 14 अप्रैल को वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर हादसे में 25 श्रमिकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से प्लांट की कार्यप्रणाली और श्रमिकों के भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब रोजगार समाप्त किए जाने के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि, मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

हटरी चौक - सुभाष चौक का जाम छोड़कर 'कैनाल रोड' पर क्यों दौड़ रहा विकास का बुलडोजर?

गरीब उजड़ेंगे और अमीर पनपेंगे'

रायगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ में पिछले दो ढाई साल से विकास के नाम पर 'ज़मीन' का अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। शहर के बाहर उद्योगों के नाम पर गांव के गांव साफ़ हो रहे हैं तो, शहर के भीतर गरीब और कमजोरों की बस्तियां उजाड़ दी जा रही है। फिलहाल हम आज बात रायगढ़ शहर की करेंगे.. एक साल पहले ठीक इसी समय 'प्रगति नगर कांड' तो सबको याद होगा.. किस तरह जुटमिल के नए मालिकों के हाउसिंग प्रोजेक्ट के जरूरी 'सड़क' लिए बर्बरता से दशकों पुरानी बस्ती ही साफ कर दी गई.. और आज बारी इंदिरा नगर जोगीडीपा बस्ती की है!

वही पैटर्न 'गरीब उजड़ेंगे और अमीर पनपेंगे'-कहानी और पैटर्न फिर से वही है.. 'गरीब उजड़ेंगे और अमीर पनपेंगे!' उस समय प्रगति नगर बस्ती को 'मरीन ड्राइव' का नाम देकर विकास का बुलडोजर चला दिया गया तो अब जोगीडीपा मे 'कैनाल लिंक रोड' के नाम से वही 'बुलडोजर' वापस आ रहा है। इस बार भी वही आरोप है, रसूखदार कॉलोनाइजर और सहभागी मित्रों की जमीन को चौड़ा रास्ता और तगड़े मुआवजे का खेल! इस बार प्लान थोड़ा अपग्रेड है.. इस बार 'साहब' के मित्रों को सरकारी रकम के लीगल बंदरबाट से एक्स्ट्रा इंकम भी होगी!

विरोध..?-ऐसा नहीं कि इस बार विरोध नहीं हुआ, सैकड़ो प्रभावित लोग निगम दफ्तर पहुंचे, मिन्नते की! लेकिन प्रगति नगर कांड से सबक लेकर और राजनीतिक नौटंकी के आगे उन्होंने हार मान ली! चुपचाप शहर से बाहर शासन की दी हुई विरान पड़े मकानों मे फिर से दोबारा शुरुआत करने का निर्णय ले लिया हैज विस्थापन का कार्य हो रहा है निगम प्रशासन भी मदद कर रहा है।

रहस्यमई रायगढ़ कांग्रेस और भाजपा की 'पितामहीं मजबूरी'- राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस का 'विरोध' एक पानी का बुलबुला है, जो सतह पर आने से पहले ही खत्म हो जाता है! सत्ता में बैठे फायदेमंद चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी भाजपा नेताओ (जिनके मुंह में आवाज थी) की स्थिति तो 'भीष्म पितामह' जैसी है जो अपने ही प्रतिज्ञा और वचन से बंधे हैं और ना चाहते हुए भी दुर्योधन का साथ देना है.. चाहे सामने अपने या भगवान ही क्यों ना हो! कांग्रेस ने इस बार विरोध के नाम पर ज्वाइंट कमेटी बनाकर मामले की जांच की बात कही.. जांच भी हुई मगर जांच में क्या निकला..?? किसी को कोई पता नहीं! यह आज भी एक रहस्य है, कहा जाता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा गया है! कहावत वही है 'जंगल में मोर नाचा किसने देखा..! **'एक सवाल आखिर कब..?-**फिलहाल.. 'वे चुपचाप जा रहे हैं!' अपने दशकों पुराने आशियानों को छोड़कर.. मकान छोटा था, सुविधा नहीं थी.. मगर उनका बचपन, उनके पुरखों की यादे थी.. . अब सब सड़क पर होगी! पता नहीं इस सड़क से अब किसका कितना फायदा होगा.. रायगढ़ का कितना ट्रैफिक बोझ कम होगा..? यहां के विधायक और कथित विकास पुरुष ओपी चौधरी तो नए-नए हैं, लेकिन बात सड़क और जाम कि है तो रायगढ़ पुराने बाशिंदों के मन में एक सवाल हमेशा से है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।